[2024] 5 एस.सी.आर. 761: 2024 आईएनएससी 387

विधि विरुद्ध बालक अपनी माँ के माध्यम से

बनाम

कर्नाटक राज्य और अन्य

(2024 की आपराधिक अपील संख्या 2411)

07 मई 2024

[सी.टी. रविकुमार और राजेश बिंदल,* न्यायमूर्तिगण]

विचार के लिए मुद्दा

(i) क्या किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 14(3) के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन पूरा करने के लिए प्रदान की गई अवधि अनिवार्य है या निर्देशात्मक; (ii) क्या किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 और 2016 के नियमों में 'बाल न्यायालय' और 'सत्र न्यायालय' शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर पढ़ा जाएगा; (iii) अधिनियम की धारा 15 के तहत पारित बोर्ड के आदेश के खिलाफ अधिनियम की धारा 101(2) के तहत अपील दायर करने की समय अवधि क्या है; (iv) क्या न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, बोर्डों और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा पारित सभी आदेशों में पीठासीन अधिकारी और/या आदेशों पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के नाम का उल्लेख किया जाएगा; (v) क्या पीठासीन अधिकारी और/या सदस्य आदेश पारित करते समय पक्षकारों और/या उनके वकीलों की उपस्थिति, जिस उद्देश्य के लिए मामला स्थगित किया जा रहा है तथा जिस पक्षकार की ओर से स्थगन मांगा गया है और दिया गया है, उसका समुचित अभिलेख दर्ज करेंगे।

हेडनोट्स†

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 – धारा 14(3) – क्या अधिनियम 2015 की धारा 14(3) के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन पूरा करने के लिए प्रदान की

गई अवधि अनिवार्य है या निर्देशात्मक:

निर्णय: अधिनियम की धारा 15(1) के अनुसार बोर्ड द्वारा जघन्य अपराध का प्रारंभिक आकलन अधिनियम की धारा 14(3) के अनुसार तीन महीने की अवधि के भीतर समाप्त किया जाना है – अधिनियम में समय के विस्तार का प्रावधान नहीं है और यह अनुमेय समय के भीतर जांच पूरी न करने के परिणाम भी निर्धारित नहीं करता है – इसके अभाव में जांच पूरी करने की समय सीमा निर्धारित करने वाला प्रावधान अनिवार्य नहीं माना जा सकता है – इस प्रकार, अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रारंभिक आकलन पूरा करने के लिए तीन महीने की अवधि प्रदान करने वाला अधिनियम की धारा 14(3) का प्रावधान अनिवार्य नहीं है – इसे निर्देशात्मक माना गया है – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या, जैसा भी मामला हो, मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से अवधि बढ़ाई जा सकती है – चूंकि प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया में कई व्यक्ति शामिल होते हैं, अर्थात जांच अधिकारी, विशेषज्ञ जिनकी राय प्राप्त की जानी है, और उसके बाद बोर्ड के समक्ष कार्यवाही, जहां विभिन्न कारणों से किसी भी पक्ष कार्यवाही में देरी करने में सक्षम होने के कारण, धारा 14(3) में प्रदान किया गया समय अनिवार्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें विफलता के कोई परिणाम प्रदान नहीं किए गए हैं, जैसा कि अधिनियम की धारा 14(4) के अनुसार छोटे अपराधों की जांच के मामले में है। [पैरा 9.13, 9.14, 18(i)]

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 - किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 - क्या किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 और 2016 के नियमों में 'बाल न्यायालय' और 'सत्र न्यायालय' शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर पढ़ा जाएगा:

निर्णय: अधिनियम और 2016 के नियमों के प्रावधानों के संयुक्त वाचन से, जहां कहीं भी 'बाल न्यायालय' या 'सत्र न्यायालय' शब्दों का उल्लेख किया गया है, दोनों को वैकल्पिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए - इस अर्थ में कि जहां बाल न्यायालय उपलब्ध है, भले ही अपील को

सत्र न्यायालय के समक्ष बनाए रखने योग्य कहा जाता है, इसे बाल न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए - जबकि जहां कोई बाल न्यायालय उपलब्ध नहीं है, वहां सत्र न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाना है - किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और 2016 के नियमों में 'बाल न्यायालय' और 'सत्र न्यायालय' शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर पढ़ा जाएगा - मुख्य रूप से अधिकार क्षेत्र बाल न्यायालय में निहित है - हालांकि, जिले में ऐसे बाल न्यायालय के गठन की अनुपस्थिति में, अधिनियम के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति सत्र न्यायालय में निहित है। [पैरा 12.2, 18 (ii)]

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 - अधिनियम की धारा 15 के तहत पारित बोर्ड के आदेश के खिलाफ अधिनियम की धारा 101 (2) के तहत अपील दायर करने की समय अवधि क्या है:

निर्णय: अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत पारित बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 101(2) के अंतर्गत अपील 30 दिनों की अवधि के भीतर दायर की जा सकती है - अपीलीय न्यायालय उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है, बशर्ते पर्याप्त कारण दर्शाया गया हो - 30 दिनों की अवधि के भीतर दायर की गई ऐसी किसी भी अपील पर निर्णय लेने का प्रयास किया जाना चाहिए। [पैरा 18(iii)]

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 - क्या न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, बोर्डों और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा पारित सभी आदेशों में पीठासीन अधिकारी और/या आदेशों पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के नाम का उल्लेख किया जाएगा:

निर्णय: न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, बोर्डों और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा पारित सभी आदेशों में पीठासीन अधिकारी और/या आदेशों पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के नाम का उल्लेख किया जाएगा - यदि कोई पहचान संख्या दी गई है, तो उसे भी जोड़ा जा सकता है। [पैरा 18(vii)]

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 - क्या पीठासीन अधिकारी और/या सदस्य आदेश पारित करते समय पक्षकारों और/या उनके वकीलों की उपस्थिति, जिस उद्देश्य से मामले को स्थगित किया जा रहा है और जिस पक्ष की ओर से स्थगन मांगा गया है और दिया गया है, उसे उचित रूप से दर्ज करेंगे:

निर्णय: पीठासीन अधिकारी और/या सदस्य आदेश पारित करते समय पक्षकारों और/या उनके वकीलों की उपस्थिति, जिस उद्देश्य से मामले को स्थगित किया जा रहा है और जिस पक्ष की ओर से स्थगन मांगा गया है और दिया गया है, उसे उचित रूप से दर्ज करेंगे। [पैरा 18(viii)]

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 – धारा। 7, 3 – किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 – विधि विरुद्ध बालक (सीसीएल) के खिलाफ धारा 376(i), 342 आईपीसी और धारा 4, 5, 6, 7 और 8 पोक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई – इस बात को लेकर दलीलें कि क्या सीसीएल पर बोर्ड द्वारा या बच्चों के न्यायालय द्वारा एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना है, प्रधान मजिस्ट्रेट और बोर्ड के सदस्य द्वारा सुनी गईं – मामले को आदेश के लिए 05.04.2022 तक स्थगित कर दिया गया – 05.04.2022 को, बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट ने एक आदेश पारित किया कि प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट और सामाजिक जांच रिपोर्ट के अनुसार, सीसीएल पर बच्चों के न्यायालय द्वारा एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना है – हालांकि, जब फाइल को बोर्ड के सदस्य के समक्ष हस्ताक्षर के लिए रखा गया, तो उन्होंने दर्ज किया कि 12.04.2022 को, प्रधान मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के बिना बोर्ड के दो सदस्यों द्वारा मामले की नए सिरे से सुनवाई की गई – आदेश पारित किया गया कि प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट और सामाजिक जांच रिपोर्ट के अनुसार, सीसीएल द्वारा किए गए कथित अपराध के संबंध में जांच बोर्ड द्वारा किशोर के रूप में की जानी है – शुद्धता:

निर्णय: अधिनियम की धारा 7 बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया से संबंधित है – इसकी उप-धारा 3 में प्रावधान है कि बोर्ड बोर्ड के किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति के बावजूद कार्य कर सकता है – बोर्ड द्वारा पारित कोई भी आदेश कार्यवाही के किसी भी चरण के दौरान किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण ही अमान्य नहीं होगा – इसके प्रावधान में प्रावधान है कि मामले के अंतिम निपटारे या अधिनियम की धारा 18(3) के तहत आदेश देने के समय, प्रधान मजिस्ट्रेट सहित कम से कम दो सदस्य मौजूद होंगे – अधिनियम की धारा 7(4) में प्रावधान है कि यदि अंतरिम या अंतिम निपटारे में कोई मतभेद है, तो बहुमत की राय मान्य होगी – जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां प्रधान मजिस्ट्रेट की राय मान्य होगी – रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि 29.03.2022 को आदेश सुरक्षित रखे जाने के बाद, मामले को 05.04.2022 को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया गया था इस तरह के कोई विस्तृत कारण नहीं दिए गए थे - ऐसी स्थिति में प्रधान मजिस्ट्रेट की राय मान्य होगी - वर्तमान मामले में आदेश पर प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे - भले ही बोर्ड के अन्य सदस्य ने आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किए हों और केवल उल्लेख किया हो कि उनके पास असहमति का दृष्टिकोण है, बिना किसी कारण को दर्ज किए, प्रधान मजिस्ट्रेट का आदेश मान्य होगा - इस प्रकार, 05.04.2022 को प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित बोर्ड द्वारा पारित आदेश अंतिम था। [पैरा 15.2, 15.4, 15.5]

कानून पर भारोसा किया गया

टॉपलाइन शूज लिमिटेड बनाम कॉर्पोरेशन बैंक [2002] 3 एससीआर 1167: **(2002) 6 एससीसी 33: 2002 आईएनएससी 287;** कैलाश बनाम नन्हकू और अन्य [2005] 3 एससीआर 289: **(2005) 4 एससीसी 480: 2005 आईएनएससी 186;** बिहार राज्य और अन्य बनाम बिहार राज्य भूमि विकास बैंक समिति [2018] 7 एससीआर 1147: **(2018) 9 एससीसी 472: 2018 आईएनएससी 648;** सी. ब्राइट बनाम जिला और अन्य [2020] 7

एससीआर 997: **(2021) 2 एससीसी 392: 2020 आईएनएससी 633 - पर भरोसा किया गया।**

भोला बनाम मध्य प्रदेश राज्य **(2019) एससीसी ऑनलाइन एमपी 521;** नीरज और अन्य बनाम हरियाणा राज्य **(2005) एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 611;** एक्स बनाम राज्य **(2019) एससीसी ऑनलाइन डेल 11164;** सीसीएल बनाम दिल्ली राज्य (एनसीटी) **(2023) एससीसी ऑनलाइन डेल 5063 – स्वीकृत।**

बालाजी बलिराम मुपड़े एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य **(2021) 12 एससीसी 603;** बरुन चंद्र ठाकुर बनाम मास्टर भोलू एवं अन्य [2022] 10 एससीआर 595 : **2022 आईएनएससी 716;** शिल्पा मित्तल बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) [2020] 2 एससीआर 478 : **(2020) 2 एससीसी 787 : 2020 आईएनएससी 25;** एससीजी कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम के.एस. चमनकर इंफ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड [2019] 3 एससीआर 1050 : **(2019) 12 एससीसी 210 : 2019 आईएनएससी 187;** एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एवं अन्य बनाम चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य (2010) 8 एससीआर 1053 : **(2010) 8 एससीसी 24 : 2010 आईएनएससी 431;** सुरजीत सिंह कालरा बनाम भारत संघ एवं अन्य [1991] 1 एससीआर 364 : **(1991) 2 एससीसी 87 : 1991 आईएनएससी 36;** राजबीर सिंह दलाल (डॉ.) बनाम चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा एवं अन्य [2008] 11 एससीआर 992 : **(2008) 9 एससीसी 284 : 2008 आईएनएससी 913;** केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बैंक प्रतिभूति और धोखाधड़ी प्रकोष्ठ बनाम रमेश गेली और अन्य [2016] 1 एससीआर 762: **(2016) 3 एससीसी 788: 2016 आईएनएससी 134 – संदर्भित।**

पुस्तक एवं पीरियोडिकल्स पर भरोसा किया

न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, 9वां संस्करण, पृ.71-76 – **संदर्भित।**

अधिनियमों की सूचि

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015; किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016

मुख्य शब्दों की सूची

विधि विरुद्ध बालक (सी सी एल); किशोर न्याय; बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट; प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट; सामाजिक जांच रिपोर्ट; किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 14(3) के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन; बाल न्यायालय और सत्र न्यायालय; किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 101(2) के तहत अपील दायर करने की समय अवधि; पक्षों और/या उनके वकीलों की उपस्थिति दर्ज करना।

से उत्पन्न मामाला

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2024 की आपराधिक अपील संख्या 2411

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु के 2023 की सीआरएलआरपी संख्या 1243 के दिनांक 15.11.2023 के निर्णय एवं आदेश से

पक्षकारों के लिए उपस्थिति

एस नागामुथु, सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ वकील, सुश्री साक्षी कक्कड़, शक्ति सिंह, आर कार्तिक, टी हरि, अपीलार्थी के लिए अधिवक्तागण।

अमन पंवार, ए.ए.जी., वी.एन. रघुपति, मनेंद्र पाल गुप्ता, शिवम सिंह बघेल, हर्ष गट्टानी, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्तागण।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय / आदेश

राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति

अनुमति प्रदान की गई।

संक्षिप्त तथ्य

2. वर्तमान अपील विधि विरुद्ध बच्चे[1] द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश[2] को चुनौती देते हुए दायर की गई है[3]।

3. उपरोक्त आदेश के तहत उच्च न्यायालय ने बोर्ड[4] द्वारा पारित दिनांक 10.04.2023 के आदेश को रद्द कर दिया।

4. संक्षेप में, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्य यह हैं कि सी.सी.एल. के खिलाफ एफ.आई.आर.[5] आई.पी.सी. की धारा 376 (आई), 342 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012[6] की धारा 4,5,6,7 और 8 के तहत अपराध करने के लिए दर्ज की गई थी। 03.11.2021 को उनकी गिरफ्तारी के बाद, सीसीएल को बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। 09.11.2021 पर, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। बोर्ड को इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था कि क्या सी.सी.एल. पर बोर्ड द्वारा मुकदमा चलाया जाना है या बाल न्यायालय द्वारा वयस्क के रूप में। प्रधान मजिस्ट्रेट और बोर्ड के एक सदस्य द्वारा मामले में दलीलें 29.03.2022 पर सुनी गईं। आदेश के लिए मामले को 05.04.2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

4.1 दिनांक 05.04.2022 को बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट ने एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट और सामाजिक जांच रिपोर्ट के अनुसार, सीसीएल पर बाल न्यायालय द्वारा वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना है। रिकॉर्ड को संबंधित न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, जब फ़ाइल को बोर्ड के सदस्य के समक्ष हस्ताक्षर के लिए रखा गया, तो उन्होंने दर्ज किया: "मैं उपरोक्त

---

[1] इसके बाद इसे "सी.सी.एल" कहा जाएगा

[2] आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 1243/2023 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2023

[3] कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु

[4] अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड, बैंगलोर शहर

[5] अपराध क्रमांक 239/2021 दिनांक 03.11.2021.

[6] इसके बाद इसे "2012 अधिनियम" कहा जाएगा।

आदेश से असहमत हूँ। मैं अगली सुनवाई की तारीख पर विस्तृत आदेश पारित करूँगा।" मामले को 12.04.2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बोर्ड के सदस्य द्वारा 05.04.2022 को दर्ज किए गए अनुसार कोई अलग आदेश उनके द्वारा पारित नहीं किया गया था। 12.04.2022 को मामले की सुनवाई बोर्ड के दो सदस्यों द्वारा प्रधान मजिस्ट्रेट की मौजूदगी के बिना फिर से की गई। आदेश पारित किया गया कि प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट और सामाजिक जांच रिपोर्ट के अनुसार, सीसीएल द्वारा किए गए कथित अपराध के संबंध में जांच बोर्ड द्वारा किशोर के रूप में की जानी है।

4.2 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015[7] की धारा 19 के तहत दिनांक 18.10.2022 को शिकायतकर्ता/पीड़िता की मां द्वारा बोर्ड के समक्ष कार्यवाही समाप्त करने और मामले को बाल न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जिस पर सीसीएल द्वारा आपत्तियां दर्ज की गई थीं।

4.3 10.4.2023 दिनांकित आदेश के माध्यम से, बोर्ड ने आवेदन को खारिज कर दिया।

4.4 उपरोक्त आदेश का विरोध करते हुए, पुनरीक्षण याचिका[8] शिकायतकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 10.04.2023 के विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया। बोर्ड को निर्देश दिया गया कि वह रिकॉर्ड को सुनवाई के लिए बाल न्यायालय को सौंप दे।

4.5 उपरोक्त आदेश सी. सी. एल. द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन है।

अपीलकर्ता की दलीलें

5. सीसीएल की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ लूथरा और श्री एस. नागमुथु ने प्रस्तुत किया कि बिना कारण बताये आदेश पारित करने की प्रथा को इस

[7] इसके बाद इसे "अधिनियम" कहा जाएगा

[8] आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 1243/2023

न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किया गया है। यह संबंधित पक्ष को उसके उचित उपचार का लाभ उठाने से वंचित करता है, जब कोई कारण उपलब्ध नहीं होता है। इस मामले में, सबसे पहले प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ने उल्लेख किया कि यह आदेश उनके और बोर्ड के एक अन्य सदस्य द्वारा पारित किया जा रहा है। हालाँकि, बोर्ड के सदस्य ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। उन्होंने केवल यह उल्लेख किया कि वे प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के विचारों से असहमत हैं और अगली तारीख को एक विस्तृत आदेश पारित करेंगे। मामले को 12.04.2022 के लिए रखा गया था। तर्कों के समर्थन में, **बालाजी बलिराम मुपड़े और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य**[9] में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया था।

5.1 यह आगे तर्क दिया गया कि 05.04.2022 पर पारित आदेश कानून की नजर में एक आदेश नहीं है। यह मामला 12.04.2022 पर सूचीबद्ध होने के कारण, बोर्ड के दो सदस्यों द्वारा दलीलें सुनी गईं, जिनमें वह सदस्य भी शामिल था जिसने पहले आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। एक आदेश पारित किया गया था जिसमें निर्देश दिया गया था कि अपराध की जांच बोर्ड द्वारा की जाएगी, जिसमें सी.सी.एल. को किशोर माना जाएगा। उन्होंने आगे सीआरएल एम.पी. संख्या 28749/2024 के साथ रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों का हवाला दिया कि यहां तक कि प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट भी उस तारीख को अदालत में मौजूद थे। उन्होंने दलीलें भी सुनी थीं लेकिन आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। 12.04.2022 पर एक सुविचारित आदेश पारित किया गया था, जिसके खिलाफ पीड़ित के लिए एकमात्र उपाय अपील दायर करना था। हालाँकि, अधिनियम की धारा 101 के तहत प्रदान की गई अवधि के भीतर इसका लाभ नहीं उठाया गया था।

5.2 आगे यह भी कहा गया कि बोर्ड के समक्ष सुनवाई शुरू होने के लगभग छह महीने बाद बोर्ड के समक्ष कार्यवाही समाप्त करने और मामले को बाल न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया, जिस पर सीसीएल द्वारा आपत्तियां

---

[9] (2021) 12 एससीसी 603

दर्ज की गईं। बोर्ड ने कानून की स्थिति को सही ढंग से समझा और पीड़िता की मां द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया।

5.3 यह प्रस्तुत किया गया कि भले ही तर्कों के लिए यह मान लिया जाए कि 12.04.2022 को पारित आदेश कानूनी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता, यह अधिक से अधिक 05.04.2022 के आदेश को पुनर्जीवित कर सकता है जिसके खिलाफ सीसीएल के पास अपील दायर करने का उपाय है। हालांकि, 12.04.2022 को आदेश पारित होने के बाद से हुए घटनाक्रमों को देखते हुए, सीसीएल को अपील के अपने उपाय से वंचित कर दिया गया है। यदि इस न्यायालय का विचार है कि 05.04.2022 को पारित आदेश एक आदेश था, तो सीसीएल को उसके खिलाफ अपील का उपाय प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा आपत्तिजनक आदेश पारित करने के साथ, सीसीएल को आदेश के खिलाफ उपायहीन छोड़ दिया गया है।

5.4 अधिनियम की धारा 15(1) सी.सी.एल. की मानसिक स्थिति और शारीरिक क्षमता के बारे में प्रारंभिक मूल्यांकन का प्रावधान करती है, जिसने कथित रूप से जघन्य अपराध किया था। यदि बोर्ड संतुष्ट होता है कि मामले की जांच बोर्ड द्वारा की जानी है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा। हालाँकि, बाल न्यायालय द्वारा सीसीएल के परीक्षण के लिए अधिनियम की धारा 18(3) के तहत भी आदेश पारित किया जा सकता है। यह केवल मूल्यांकन है कि बोर्ड या बाल न्यायालय को जांच करनी है या मुकदमा चलाना है।

5.5 अधिनियम की धारा 18 (3) में प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद, बोर्ड एक आदेश पारित करेगा कि वयस्क के रूप में सी.सी.एल. के परीक्षण की आवश्यकता है। मुकदमे के अभिलेखों को सुनवाई के लिए बाल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

5.6 अधिनियम की धारा 17 में बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया का प्रावधान है। यह प्रस्तुत किया गया था कि बोर्ड एक अदालत नहीं है और बोर्ड द्वारा की गई किसी भी

कार्यवाही को आदेश के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। यह केवल एक राय है। अधिनियम की धारा 2(10) में परिभाषित बोर्ड का अर्थ है उसकी धारा 4 के तहत गठित बोर्ड। इसमें एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, जो कम से कम तीन साल के अनुभव के साथ मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं होगा और निर्धारित तरीके से चुने गए दो सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जिनमें से एक महिला होनी चाहिए।

5.7 अधिनियम की धारा 7(3) में प्रावधान है कि किसी मामले के अंतिम निपटारे के समय प्रधान मजिस्ट्रेट सहित कम से कम दो सदस्य उपस्थित होंगे या अधिनियम की धारा 18(3) के तहत आदेश देंगे।

5.8 यह आगे प्रस्तुत किया गया कि बाल न्यायालय द्वारा सी.सी.एल. के मुकदमे का निर्देश देते हुए बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 18(3) के तहत पारित आदेश के खिलाफ अपील सत्र न्यायालय में होगी।

5.9 अधिनियम की धारा 2(20) में बाल न्यायालय शब्द को परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005[10] के तहत स्थापित न्यायालय या अधिनियम 2012 के तहत विशेष न्यायालय, और जहां ऐसे न्यायालयों को नामित नहीं किया गया है, वहां क्षेत्राधिकार रखने वाला सत्र न्यायालय। तर्क यह है कि अधिनियम की धारा 101 की उपधारा (1) और (2) में दो अलग-अलग प्राधिकरणों का उल्लेख किया गया है, अन्यथा अलग-अलग प्रावधानों की आवश्यकता नहीं थी। यह कानून की भावना है।

5.10 अधिनियम की धारा 19 बाल न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है। धारा 15 के तहत बोर्ड से प्रारंभिक मूल्यांकन प्राप्त होने के बाद, बाल न्यायालय यह निर्णय ले सकता है कि बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए या वयस्क के रूप में

[10] इसके बाद इसे "2005 अधिनियम" कहा जाएगा

सीसीएल के मुकदमे की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिनियम की धारा 101(5) के अनुसार बाल न्यायालय द्वारा पारित आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष अपील योग्य है।

5.11 **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016**[11] के नियम 10ए का संदर्भ दिया गया, जिसमें धारा 14 के तहत किशोर किशोर की आयु के संबंध में प्रारंभिक आकलन और अधिनियम की धारा 15 के तहत बोर्ड द्वारा जांच या बाल न्यायालय द्वारा सुनवाई की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

5.12 अधिनियम की उपरोक्त योजना का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिनियम की धारा 15 के तहत एक मूल्यांकन एक आदेश पारित करने की परिकल्पना नहीं करता है। यह केवल दर्ज की गई संतुष्टि है, और बोर्ड द्वारा 05.04.2022 पर कोई अंतिम संतुष्टि दर्ज नहीं की गई है क्योंकि सुनवाई की अगली तारीख दी गई थी। बोर्ड को बाद में इस मामले पर विचार करना पड़ा। वास्तव में, अधिनियम की धारा 18(3) के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। बोर्ड द्वारा पारित बाद के आदेशों से पता चला कि जांच पहले ही शुरू हो चुकी थी। बाद के चरण में शिकायतकर्ता ने बोर्ड के समक्ष कार्यवाही को समाप्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे 10.04.2023 पर खारिज कर दिया गया। आदेश अधिनियम की धारा 101(1) के तहत अपील योग्य था। हालांकि, कोई याचिका दायर नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष सीआरपीसी की धारा 397 सहपठित धारा 399 के तहत पुनरीक्षण दायर किया गया था, जो स्वीकार्य नहीं था।

5.13 यह भी तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 14(3) के संदर्भ में इसकी धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन, बोर्ड के समक्ष सी.सी.एल. के पहले पेश किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। हाथ में मामले में, बच्चे को पहली बार 03.11.2021 पर बोर्ड के सामने पेश किया गया था। तीन महीने की अवधि 02.02.2022 पर समाप्त हो गई। बोर्ड द्वारा 05.04.2022 को कोई आदेश पारित नहीं किया

[11] इसके बाद इन्हें "2016 नियम" कहा जाएगा

जा सका। इसका परिणाम यह है कि सीसीएल पर बोर्ड द्वारा मुकदमा चलाया जाना है और उसके बाद बाल न्यायालय द्वारा उसके मुकदमे के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जा सका।

5.14 इस न्यायालय के **बरुन चंद्र ठाकुर बनाम मास्टर भोलू एवं अन्य**[12] के निर्णय पर भरोसा करते हुए यह प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय ने यह राय व्यक्त की है कि अधिनियम के तहत प्रदान की गई समयसीमा का पालन किया जाना चाहिए। यदि धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए धारा 14(3) में प्रदान की गई समयसीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता है, तो बाल न्यायालय द्वारा सीसीएल के परीक्षण के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। **शिल्पा मित्तल बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली)**[13] में इस न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया गया।

प्रतिवादियों के तर्क

6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बोर्ड द्वारा मामले को बाल न्यायालय में सी.सी.एल. के परीक्षण के लिए स्थानांतरित करने का आदेश पारित किए जाने के बाद भी, अधिनियम की धारा 19(1) के तहत बाल न्यायालय द्वारा इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। बाल न्यायालय द्वारा पारित कोई भी आदेश अधिनियम की धारा 101(5) के तहत अपील योग्य है। धारा 101(1) और 101(2) का दायरा अलग-अलग है। उप-धारा (1) अंतिम आदेशों से संबंधित है, जबकि उप-धारा (2) प्रारंभिक मूल्यांकन से संबंधित है। अपराध का परीक्षण केवल बाल न्यायालय द्वारा किया जाता है।

6.1 यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम की धारा 15 (1) के प्रावधान के संदर्भ में, बोर्ड अनुभवी मनोवैज्ञानिकों, मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है ताकि बोर्ड एक उचित निष्कर्ष पर पहुँच सके।

---

[12] 2022 आईएनएससी 716: (2022) 10 एससीआर 595

[13] (2020) 2 एससीसी 787: 2020 आईएनएससी 25: (2020) 2 एससीआर 478

6.2 इस मामले में, निमहंस-डीडब्ल्यूसीओ के बाल एवं किशोर मनोचिकित्सा विभाग द्वारा दिनांक 01.02.2022 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। यह पुलिस निरीक्षक, मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन द्वारा मनोचिकित्सक, निमहंस अस्पताल, बेंगलुरु को दिनांक 12.01.2022 को लिखे गए पत्र के जवाब में था। पीछे जाकर, राज्य के विद्वान वकील ने बोर्ड के दिनांक 09.11.2021 के अंतरिम आदेश का हवाला दिया, जिसके अनुसार बोर्ड ने अधिनियम की धारा 18(3) के अनुसार बोर्ड को आगे का आदेश पारित करने में सक्षम बनाने के लिए बच्चे की सामाजिक जांच रिपोर्ट मांगी थी। हालाँकि, 06.12.2021 को कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। मामले को 06.12.2021 से 11.01.2022 तक और उसके बाद 21.02.2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सामाजिक जांच रिपोर्ट बोर्ड को 19.02.2022 को प्राप्त हुई।

6.3 सी.सी.एल. पर बाल न्यायालय द्वारा सुनवाई या बोर्ड द्वारा जांच के मुद्दे पर बहस 29.03.2022 को पूरी हो गई थी और मामले को आदेश के लिए 05.04.2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, जब प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ने बाल न्यायालय द्वारा सी.सी.एल. पर सुनवाई के लिए निर्देश देने वाला आदेश पारित किया। बोर्ड के एक अन्य सदस्य ने अपने हस्ताक्षर नहीं किए और दर्ज किया कि उनका असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण है और वे अगली तारीख यानी 12.04.2022 को विस्तृत आदेश पारित करेंगे। वास्तव में, अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार, फोरम के निर्धारण की कार्यवाही, जिसे जांच या सुनवाई का संचालन करना था, उसी दिन समाप्त हो गई, क्योंकि प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट की राय अंतिम होती है। जिस तरह से मामले को बाद में निपटाया गया, वह अजीब है। 12.04.2022 के बाद के आदेश बोर्ड के विभिन्न सदस्यों द्वारा पारित किए गए थे। संपूर्ण कार्यवाही अवांछित थी। बोर्ड के समक्ष कार्यवाही समाप्त करने और मामले को बाल न्यायालय को संदर्भित करने के लिए पीड़िता द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कोई त्रुटि नहीं थी, जिसके लिए प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा 05.04.2022 को पहले ही आदेश पारित किया जा चुका था।

6.4 यह आगे तर्क दिया गया कि केवल इसलिए कि अधिनियम की धारा 15 के तहत कार्यवाही तीन महीने के भीतर समाप्त नहीं की जा सकी, डिफ़ॉल्ट रूप से सी.सी.एल. पर बोर्ड द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इस प्रावधान को अनिवार्य नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि अधिनियम में इस तरह की चूक का कोई परिणाम प्रदान नहीं किया गया है। यहां तक कि धारा 14(4) के परंतुक में भी समय बढ़ाने का प्रावधान है यदि धारा 14 (1) के तहत परिकल्पित जांच निर्धारित समय के भीतर समाप्त नहीं की जा सकती है।

6.5 आगे यह भी कहा गया कि यद्यपि अधिनियम की धारा 14(3) से संबंधित इस मामले में इस न्यायालय का कोई सीधा निर्णय नहीं है। फिर भी, राज्य के विद्वान वकील ने मध्य प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा तथा दिल्ली उच्च न्यायालयों के निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया: **भोला बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[14], **नीरज एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य**[15] तथा **एक्स बनाम राज्य**[16]**।**

6.6 आगे यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 15 के तहत परिकल्पित जांच अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों से राय लेने का प्रावधान करती है। जाँच अधिकारी की भूमिका भी प्रासंगिक है क्योंकि वह उसी की जाँच कर रहा है। लाभ लेने के लिए भी प्रक्रिया में जानबूझकर देरी हो सकती है, यदि डिफ़ॉल्ट रूप से सी.सी.एल. पर एक जघन्य अपराध में बोर्ड द्वारा मुकदमा चलाया जाना है। जैसा कि मामले में जांच अधिकारी को खुद निमहान्स से रिपोर्ट प्राप्त करने में लगभग दो महीने का समय लगा। ऐसी स्थिति में बोर्ड को कारण दर्ज करने के लिए समय बढ़ाने के लिए शक्तिहीन नहीं माना जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे मामले में सभी कार्यवाहियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।

---

[14] 2019 एससीसी ऑनलाइन एमपी 521

[15] 2005 एससीसी ऑनलाइन पी&एच 611

[16] 2019 एससीसी ऑनलाइन डेल 11164

6.7 यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों में कोई दम नहीं है, जिससे उसे 05.04.2022 के आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी जा सके, यदि उसके पास इसके खिलाफ कोई शिकायत है। उसके बाद बहुत समय निकाल चुका है। उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए पुनरीक्षण में सभी संभावित तर्क उठाए गए और उन पर विचार किया गया। अपीलकर्ता को निचले प्राधिकारी के समक्ष इसे उठाने की स्वतंत्रता देना व्यर्थ होगा। इससे प्रक्रिया में और देरी होगी। प्रार्थना अपील को खारिज करने की है।

चर्चा

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनवाई की गई तथा संबंधित संदर्भित अभिलेख का अवलोकन किया गया। हमने अपने निर्णय को विभिन्न भागों में विभाजित किया है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

क्रम सं.	**शीर्षक**	**पैरा संख्या(एँ)**	**पृष्ठ संख्या(एँ)**
I	प्रासंगिक प्रावधान	8	16-37
II	क्या अधिनियम की धारा 14(3) के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन पूरा करने के लिए प्रदान की गई अवधि अनिवार्य है या निर्देशिका?	9-9.28	37-57
III	उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग।	10-10.5	58-61
IV	किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 101 में विसंगति। क. 'बाल न्यायालय' और 'सत्र न्यायालय' जैसे शब्दों के संबंध में ख. अधिनियम की धारा 15 के तहत बोर्ड के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का समय	 11-12.2 13-13.2	 62-66 66-67

	ग. द्वितीय अपील के संबंध में।	14-14.1	67-68
V	बोर्ड द्वारा दिनांक 05.04.2022 को पारित आदेश की वैधता।	15-15.5	68-71
VI	अपीलकर्ता के लिए अपील का उपाय	16-16.2	71-72
VII	अतिरिक्त मुद्दे	17-17.3	72-74
VIII	राहतें और निर्देश	18-19	74-77

I. संबंधित प्रावधान

8. विभिन्न कानूनों और नियमों के प्रासंगिक प्रावधान इस मामले में लागू होने वाले निष्कर्ष नीचे दिए गए हैंः

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंशः

"धारा 2(10). "बोर्ड" का अर्थ है धारा 4 के तहत गठित किशोर न्याय बोर्ड।

धारा 2(13). "विधि विरुद्ध बालक" का अर्थ है ऐसा बच्चा जिस पर कोई अपराध करने का आरोप है या ऐसा पाया गया है और जिसने ऐसे अपराध के होने की तिथि को अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

धारा 2(20). "बाल न्यायालय" का अर्थ है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) के तहत स्थापित न्यायालय या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) के तहत विशेष न्यायालय, जहां कहीं भी विद्यमान हो और जहां ऐसे न्यायालयों को नामित नहीं किया गया है, अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र रखने वाला सत्र न्यायालय।

धारा 2(22). "समिति" का अर्थ है धारा 27 के तहत गठित बाल कल्याण समिति।

धारा 2(23). "न्यायालय" से ऐसा सिविल न्यायालय अभिप्रेत है, जिसे गोद लेने और संरक्षकता के मामलों में अधिकारिता प्राप्त है और जिसमें जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय और नगर सिविल न्यायालय शामिल हो सकते हैं।

धारा 2(33). "जघन्य अपराध" में वे अपराध शामिल हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या किसी अन्य वर्तमान कानून के तहत न्यूनतम सजा सात वर्ष या उससे अधिक कारावास है।

x x x

धारा 4. किशोर न्याय बोर्ड.—

(1) xx xx

(2) एक बोर्ड में कम से कम तीन साल का अनुभव रखने वाला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट जो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जिसे इसके बाद प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में संदर्भित किया गया है) नहीं होगा और दो सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे तरीके से चुने जाएंगे जो निर्धारित किया जाए, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, एक पीठ का गठन करेगी और ऐसी प्रत्येक पीठ को आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) द्वारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या, जैसा भी मामला हो, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियां होंगी।

(3) से (7) xx xx

धारा 7. बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया।

(1) & (2) xx xx

(3) बोर्ड के किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति के बावजूद बोर्ड कार्य कर सकता है और बोर्ड द्वारा पारित कोई भी आदेश कार्यवाही के किसी भी चरण के दौरान किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अमान्य नहीं होगाः

बशर्ते कि मामले के अंतिम निपटारे के समय या धारा 18 की उप-धारा (3) के तहत आदेश देने में प्रधान मजिस्ट्रेट सहित कम से कम दो सदस्य मौजूद होंगे।

(4) अंतरिम या अंतिम निपटान में बोर्ड के सदस्यों के बीच किसी भी मतभेद की स्थिति में, बहुमत की राय प्रबल होगी, लेकिन जहां ऐसा बहुमत नहीं है, वहां प्रधान मजिस्ट्रेट की राय प्रबल होगी।

x x x

धारा 14. विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में बोर्ड द्वारा जांच.--

(1) जहां विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित बालक बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है, वहां बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जांच करेगा और ऐसे बालक के संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह इस अधिनियम की धारा 17 और 18 के अधीन उचित समझे।

(2) इस धारा के अधीन जांच बालक को बोर्ड के समक्ष प्रथम बार पेश किए जाने की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी, जब तक कि बोर्ड द्वारा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा ऐसे विस्तार के लिए लिखित में कारण दर्ज करने के पश्चात् अवधि को अधिकतम 2 मास के लिए नहीं बढ़ाया जाता है।

(3) धारा 15 के तहत जघन्य अपराधों के मामले में बोर्ड द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन का निपटान बोर्ड के समक्ष बच्चे के पहले पेश होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(4) यदि छोटे अपराधों के लिए उप-धारा (2) के तहत बोर्ड द्वारा जांच विस्तारित अवधि के बाद भी अनिर्णायक रहती है, तो कार्यवाही समाप्त हो जाएगीः

बशर्ते कि गंभीर या जघन्य अपराधों के लिए, यदि बोर्ड को जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या, जैसा भी मामला हो, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए अनुमति दी जाएगी।

(5) xx xx

x x x

धारा 15. बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों का प्रारंभिक मूल्यांकन.-(1) किसी ऐसे जघन्य अपराध के मामले में, जो किसी बालक द्वारा किया गया है, जो सोलह वर्ष की आयु पूरी कर चुका है या उससे अधिक है, बोर्ड ऐसे अपराध करने की उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता और जिन परिस्थितियों में उसने कथित रूप से अपराध किया है, उनके संबंध में प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा और धारा 18 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार आदेश पारित कर सकता है:

बशर्ते कि इस तरह के मूल्यांकन के लिए बोर्ड अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक मूल्यांकन एक परीक्षण नहीं है, बल्कि कथित अपराध के

परिणामों को करने और समझने के लिए ऐसे बच्चे की क्षमता का आकलन करना है।

(2) जहां बोर्ड को प्रारंभिक मूल्यांकन पर संतोष होता है कि बोर्ड द्वारा मामले का निपटारा किया जाना चाहिए, तो बोर्ड दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के तहत समन मामले में मुकदमे के लिए, जहां तक हो सके, प्रक्रिया का पालन करेगाः

बशर्ते कि मामले के निपटारे के लिए बोर्ड का आदेश धारा 101 की उप-धारा (2) के तहत अपील योग्य होगा।

बशर्ते कि इस धारा के तहत मूल्यांकन धारा 14 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

x x x

धारा 17. बालक के संबंध में आदेश, जो विधि का उल्लंघन नहीं करता पाया गया हो।--(1) जहां बोर्ड जांच के बाद संतुष्ट हो जाता है कि उसके समक्ष लाए गए बालक ने कोई अपराध नहीं किया है, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, बोर्ड उस आशय का आदेश पारित करेगा।

(2) यदि बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट बच्चे को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, तो वह बच्चे को उचित निर्देशों के साथ समिति के पास भेज सकता है।

धारा 18. कानून का उल्लंघन करते पाए गए बच्चे के संबंध में आदेश—

(1) & (2) xx xx

(3) जहां बोर्ड धारा 15 के अधीन प्रारंभिक मूल्यांकन के पश्चात आदेश पारित करता है कि उक्त बालक पर वयस्क के रूप में विचारण की आवश्यकता है, तो

बोर्ड मामले के विचारण को ऐसे अपराधों पर विचारण करने के लिए अधिकारिता रखने वाले बालक न्यायालय को स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है।

धारा 19. बाल न्यायालय की शक्तियां— (1) धारा 15 के अधीन बोर्ड से प्रारंभिक मूल्यांकन प्राप्त होने के पश्चात् बाल न्यायालय यह निर्णय ले सकेगा कि-

(i) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधानों के अनुसार वयस्क के रूप में बालक पर विचारण की आवश्यकता है तथा बालक की विशेष आवश्यकताओं, निष्पक्ष विचारण के सिद्धांतों तथा बालक के अनुकूल वातावरण बनाए रखने पर विचार करते हुए इस धारा और धारा 21 के प्रावधानों के अधीन विचारण के पश्चात समुचित आदेश पारित करना;

(ii) बालक पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं है और वह बोर्ड के रूप में जांच कर सकता है तथा धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार समुचित आदेश पारित कर सकता है।

(2) बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अंतिम आदेश, कानून के साथ संघर्ष में एक बच्चे के संबंध में, बच्चे के पुनर्वास के लिए एक व्यक्तिगत देखभाल योजना शामिल होगी, जिसमें परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई शामिल होगी।

(3) बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि कानून का उल्लंघन करने वाले बालक को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए और उसके बाद उस व्यक्ति को जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए:

बशर्ते कि बच्चे को सुरक्षा के स्थान पर रहने की अवधि के दौरान शैक्षिक सेवाओं, कौशल विकास, वैकल्पिक चिकित्सा जैसे परामर्श, व्यवहार संशोधन चिकित्सा और मनोरोग सहायता सहित सुधारात्मक सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

(4) बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार आवधिक अनुवर्ती रिपोर्ट दी जाए, ताकि सुरक्षा के स्थान पर बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे के साथ किसी भी रूप में कोई दुर्व्यवहार न हो।

(5) उपधारा (4) के अधीन रिपोर्टें अभिलेख और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बाल न्यायालय को भेजी जाएंगी, जैसा अपेक्षित हो।

x x x

धारा 101. अपीलें-- (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन समिति या बोर्ड द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, बाल न्यायालय में अपील कर सकेगा, सिवाय समिति द्वारा पालन-पोषण देखभाल और प्रायोजन पश्चात देखभाल से संबंधित निर्णयों के, जिसके लिए अपील जिला मजिस्ट्रेट के पास होगी:

बशर्ते कि सत्र न्यायालय या जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है, यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था और ऐसी अपील पर तीस दिनों की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा 15 के तहत एक जघन्य अपराध में प्रारंभिक मूल्यांकन करने के बाद पारित बोर्ड के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय के समक्ष अपील की जाएगी और अदालत, अपील पर निर्णय लेते समय, अनुभवी मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों की सहायता ले सकती है, उन लोगों के अलावा जिनकी सहायता बोर्ड द्वारा उक्त धारा के तहत आदेश पारित करने में प्राप्त की गई है।

(3) सोलह वर्ष की आयु पूरी कर चुके या उससे अधिक आयु के बच्चे द्वारा जघन्य अपराध के अलावा अन्य अपराध करने के आरोप वाले बच्चे के संबंध में बोर्ड द्वारा किए गए बरी करने के किसी भी आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी।

(4) इस धारा के तहत अपील में पारित सत्र न्यायालय के किसी भी आदेश के खिलाफ कोई दूसरी अपील नहीं होगी।

(5) बाल न्यायालय के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

(6) & (7) xx xx

102. पुनरीक्षण- उच्च न्यायालय किसी भी समय, या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त प्राप्त आवेदन पर, किसी कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकता है जिसमें किसी समिति या बोर्ड या बाल न्यायालय या न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया हो, ऐसे किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजनार्थ और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह ठीक समझे: बशर्ते कि उच्च न्यायालय इस धारा के अंतर्गत किसी

व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना उसके प्रतिकूल कोई आदेश पारित नहीं करेगा।"

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के प्रासंगिक नियम 10, 10ए, 11 और 13 के उद्धरण

"**नियम 10. बोर्ड द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात की प्रक्रियाएं.-** (1) बोर्ड के समक्ष बालक को प्रस्तुत किए जाने पर, बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि, बालक को पकड़ने की परिस्थितियां तथा बालक द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध की रिपोर्ट, जैसा कि बालक को प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों, व्यक्तियों, एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई है, बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाएगी तथा बोर्ड बालक के संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे, जिसमें अधिनियम की धारा 17 और 18 के अंतर्गत आदेश भी शामिल हैं, अर्थात्:

(i) मामले का निपटारा करना, यदि उसकी पहली उपस्थिति के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और रिकॉर्ड पर विचार करने पर, उसका कानून के साथ टकराव में होना निराधार प्रतीत होता है या जहां बच्चे पर छोटे अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाया जाता है;

(ii) बच्चे को समिति के पास भेजना जहां बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि बच्चे को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है।

(iii) फार्म 3 में एक आदेश के माध्यम से, अगली तारीख को एक बच्चे को पूछताछ के लिए पेश करने या पेश करने के निर्देश के साथ, बच्चे को उपयुक्त व्यक्तियों या उपयुक्त संस्थानों या परिवीक्षा अधिकारियों की देखरेख या अभिरक्षा में रिहा करना; और

(iv) यदि आवश्यक हो तो बच्चे को प्रपत्र 4 में दिए गए आदेश के अनुसार जांच लंबित रहने तक बाल देखभाल संस्थान में रखने का निर्देश दिया जाएगा।

(2) जांच लंबित रहने तक रिहाई के सभी मामलों में, बोर्ड सुनवाई की अगली तारीख को प्रथम संक्षिप्त जांच के पंद्रह दिन के भीतर अधिसूचित करेगा और परिवीक्षा अधिकारी से सामाजिक जांच रिपोर्ट भी मांगेगा, या यदि परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो फार्म 5 में आदेश के माध्यम से संबंधित बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता से रिपोर्ट मांगेगा।

(3) जब बच्चा कथित रूप से जमानत पर भर्ती होने के बाद, सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, और उसकी ओर से छूट के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाता है या उसे छूट देने का पर्याप्त कारण नहीं है, तो बोर्ड, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और पुलिस स्टेशन के प्रभारी को बच्चे को पेश करने के लिए निर्देश जारी करेगा।

(4) यदि बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बालक को प्रस्तुत करने के निर्देश जारी होने के बाद भी बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो बोर्ड दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 के अन्तर्गत आदेशिका जारी करने के स्थान पर अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत समुचित आदेश पारित करेगा।

(5) ऐसे जघन्य अपराधों के मामलों में, जो किसी ऐसे बालक द्वारा किए गए हैं, जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बालक को बोर्ड के समक्ष पहली बार पेश किए जाने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर उसके द्वारा दर्ज किए गए साक्षियों के बयान

तथा जांच के दौरान तैयार किए गए अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जिसकी एक प्रति बालक अथवा बालक के माता-पिता या संरक्षक को भी दी जाएगी।

(6) छोटे या गंभीर अपराधों के मामलों में, अंतिम रिपोर्ट जल्द से जल्द बोर्ड के समक्ष दायर की जाएगी और किसी भी मामले में पुलिस को सूचना की तारीख से दो महीने की अवधि से अधिक नहीं, सिवाय उन मामलों के जहां यह उचित रूप से ज्ञात नहीं था कि अपराध में शामिल व्यक्ति एक बच्चा था, ऐसे मामले में बोर्ड द्वारा अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय बढ़ाया जा सकता है।

(7) जब किसी बच्चे से संबंधित जांच में गवाहों को परीक्षण के लिए पेश किया जाता है, जो कथित रूप से कानून के साथ टकराव में है, तो बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि जांच सख्त प्रतिकूल कार्यवाही की भावना से नहीं की गई है और यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेगा ताकि बच्चे से पूछताछ की जा सके और बच्चे के पक्ष में अनुमानों के साथ आगे बढ़ाया जा सके।

(8) कानून के साथ टकराव में कथित बच्चे की जांच करते समय और अधिनियम की धारा 14 के तहत जांच के दौरान उसका बयान दर्ज करते समय, बोर्ड बच्चे को बच्चों के अनुकूल तरीके से संबोधित करेगा ताकि बच्चे को आसानी से समझा जा सके और उसे बिना किसी डर के तथ्यों और परिस्थितियों को बताने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, न केवल उस अपराध के संबंध में जो बच्चे के खिलाफ आरोप लगाया गया है, बल्कि घर और सामाजिक परिवेश के संबंध में भी, और उस प्रभाव या अपराधों के संबंध में भी जिसके अधीन बच्चे को किया जा सकता है।

(9) बोर्ड बच्चे को पकड़ने की परिस्थितियों और उसके द्वारा किए गए कथित अपराध वाली रिपोर्ट और परिवीक्षा अधिकारी या स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन द्वारा तैयार किए गए फॉर्म 6 में सामाजिक जांच रिपोर्ट के साथ-साथ किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को ध्यान में रखेगा।

नियम 10ए. बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों का प्रारंभिक मूल्यांकन.- (1) बोर्ड प्रथमतः यह निर्धारित करेगा कि बालक सोलह वर्ष या उससे अधिक आयु का है; यदि नहीं, तो वह अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(2) जघन्य अपराधों के मामले में प्रारंभिक मूल्यांकन करने के उद्देश्य से, बोर्ड मनोवैज्ञानिकों या मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है जिन्हें कठिन परिस्थितियों में बच्चों के साथ काम करने का अनुभव है। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ऐसे विशेषज्ञों का एक पैनल उपलब्ध कराया जा सकता है, जिसकी सहायता बोर्ड द्वारा ली जा सकती है या स्वतंत्र रूप से प्राप्त की जा सकती है।

(3) प्रारंभिक मूल्यांकन करते समय, बच्चे को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए।

(4) जहां बोर्ड अधिनियम की धारा 15 के अधीन प्रारंभिक मूल्यांकन के पश्चात् यह आदेश पारित करता है कि उक्त बालक का वयस्क के रूप में परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है, तो वह इसके लिए कारण बताएगा और आदेश की प्रति बालक को तुरन्त उपलब्ध कराई जाएगी।

नियम 11. जांच पूरी करना- (1) जहां अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रारंभिक मूल्यांकन के पश्चात, किसी बालक द्वारा कथित रूप से किए गए

जघन्य अपराधों के मामले में, बोर्ड मामले का निपटान करने का निर्णय लेता है, वहां बोर्ड अधिनियम की धारा 18 में निर्दिष्ट कोई भी निपटान आदेश पारित कर सकता है।

(2) एक आदेश पारित करने से पहले, बोर्ड परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा आदेश के अनुसार तैयार किए गए प्रपत्र 6 में एक सामाजिक जांच रिपोर्ट प्राप्त करेगा, और रिपोर्ट के निष्कर्षों को ध्यान में रखेगा।

(3) बोर्ड द्वारा पारित सभी स्वभावगत आदेशों में आवश्यक रूप से संबंधित कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चे के लिए प्रपत्र 7 में एक व्यक्तिगत देखभाल योजना शामिल होगी, जिसे परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या किसी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन द्वारा बच्चे और उसके परिवार के साथ बातचीत के आधार पर तैयार किया जाएगा।

(4) जहां बोर्ड का समाधान हो जाता है कि बच्चे को विशेष गृह में रखना न तो स्वयं बच्चे के हित में है और न ही अन्य बच्चों के हित में है, बोर्ड बच्चे को सुरक्षा के स्थान पर और उसके द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीके से रखने का आदेश दे सकता है।

(5) जहां बोर्ड सलाह या चेतावनी के बाद या समूह परामर्श में भाग लेने के बाद बच्चे को रिहा करने का निर्णय लेता है या उसे सामुदायिक सेवा करने का आदेश देता है, बोर्ड द्वारा ऐसी परामर्श और सामुदायिक सेवा की व्यवस्था करने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई को आवश्यक निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं।

(6) जहां बोर्ड परिवीक्षा पर कानून के साथ टकराव में बच्चे को रिहा करने का निर्णय लेता है और उसे माता-पिता या अभिभावक या योग्य व्यक्ति की

देखभाल में रखता है, जिस व्यक्ति की हिरासत में बच्चे को रिहा किया जाता है, उसे अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए बच्चे के अच्छे व्यवहार और कल्याण के लिए फॉर्म 8 में एक लिखित वचन पत्र जमा करने की आवश्यकता हो सकती है।

(7) बोर्ड, विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बच्चे को प्रपत्र 9 में बिना किसी जमानत के व्यक्तिगत बांड निष्पादित करने पर रिहा करने का आदेश दे सकता है।

(8) बालक को उपयुक्त सुविधा या विशेष गृह में रखे जाने की स्थिति में, बोर्ड इस बात पर विचार करेगा कि उपयुक्त सुविधा या विशेष गृह बालक के माता-पिता या अभिभावक के निवास स्थान के सबसे निकट स्थित है, सिवाय इसके कि ऐसा करना बालक के सर्वोत्तम हित में न हो।

(9) बोर्ड, जहां वह किसी बच्चे को परिवीक्षा पर छोड़ता है और उसे माता-पिता या अभिभावक या योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखता है अथवा जहां बच्चे को परिवीक्षा पर छोड़ता है और उसे उपयुक्त सुविधा की देखरेख में रखता है, वह यह भी आदेश दे सकता है कि बच्चे को परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में रखा जाए जो प्रपत्र 10 में आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसे पर्यवेक्षण की अवधि अधिकतम तीन वर्ष होगी।

(10) जहां बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि बच्चे ने परिवीक्षा शर्तों का पालन नहीं किया है, वह बच्चे को उसके सामने पेश करने का आदेश दे सकता है और बच्चे को पर्यवेक्षण की शेष अवधि के लिए किसी विशेष घर या सुरक्षा स्थान पर भेज सकता है।

(11) किसी भी मामले में, विशेष घर या सुरक्षा के स्थान पर रहने की अवधि अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के खंड (जी) में प्रदान की गई अधिकतम अवधि से अधिक नहीं होगी।

x x x

नियम 13. बाल न्यायालय और निगरानी प्राधिकरणों के संबंध में प्रक्रिया.-

(1) बोर्ड से प्रारंभिक मूल्यांकन प्राप्त होने पर बाल न्यायालय यह निर्णय ले सकता है कि बच्चे पर वयस्क के रूप में या बच्चे के रूप में मुकदमा चलाने की आवश्यकता है या नहीं और उचित आदेश पारित कर सकता है।

(2) जहां बालक की आयु घोषित करने वाले बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन अपील दायर की गई है, वहां बाल न्यायालय पहले उक्त अपील का विनिश्चय करेगा।

(3) जहां बोर्ड द्वारा किए गए प्रारंभिक मूल्यांकन के निष्कर्ष के विरुद्ध अधिनियम की धारा 101 की उपधारा (2) के अंतर्गत अपील दायर की गई है, वहां बाल न्यायालय पहले अपील का निर्णय करेगा।

(4) जहां अधिनियम की धारा 101 की उपधारा (2) के अंतर्गत अपील का निपटारा बाल न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर किया जाता है कि बालक पर वयस्क के रूप में विचारण की आवश्यकता नहीं है, वहां वह उसका निपटारा अधिनियम की धारा 19 और इन नियमों के अनुसार करेगा।

(5) जहां अधिनियम की धारा 101 की उपधारा (2) के अंतर्गत अपील का निपटारा बाल न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर किया जाता है कि बालक पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, वहां बाल न्यायालय बोर्ड से मामले की फाइल मंगाएगा और अधिनियम तथा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार मामले का निपटारा करेगा।

(6) बाल न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचते समय अपने कारणों को दर्ज करेगा कि बच्चे के साथ वयस्क की तरह व्यवहार किया जाए या बच्चे की तरह।

(7) जहां बाल न्यायालय यह निर्णय लेता है कि बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वह मामले का निर्णय स्वयं करेगा:

(i) यह जांच इस प्रकार कर सकता है मानो यह एक बोर्ड के रूप में कार्य कर रहा हो और अधिनियम तथा इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार मामले का निपटारा कर सकता है।

(ii) बाल न्यायालय, जांच करते समय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत समन मामले में सुनवाई की प्रक्रिया का पालन करेगा।

(iii) कार्यवाही बंद कमरे में और बच्चों के अनुकूल माहौल में की जाएगी, तथा कानून का उल्लंघन करने वाले कथित बच्चे का किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संयुक्त परीक्षण नहीं किया जाएगा जो बच्चा नहीं है।

(iv) जब गवाहों को परीक्षा के लिए पेश किया जाता है तो बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि जांच सख्त विरोधात्मक कार्यवाही की भावना से नहीं की जाती है और वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(v) विधि से विरुद्ध किसी बालक की जांच करते समय और उसका बयान दर्ज करते समय, बाल न्यायालय बालक को सहज महसूस कराने के लिए तथा उसे बिना किसी भय के तथ्यों और परिस्थितियों

को बताने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बालक से बाल-मैत्रीपूर्ण तरीके से बात करेगा, न केवल बालक के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में, बल्कि घर और सामाजिक परिवेश तथा बालक पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में भी।

(vi) बाल न्यायालय द्वारा पारित निपटान आदेश में संबंधित विधि विरुद्ध बच्चे के लिए फॉर्म 7 में एक व्यक्तिगत देखभाल योजना शामिल होगी, जिसे परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन द्वारा, जहां संभव हो, बच्चे और उसके परिवार के साथ बातचीत के आधार पर तैयार किया जाएगा।

(vii) ऐसे मामलों में बाल न्यायालय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) और (2) के अनुसार कोई भी आदेश पारित कर सकता है।

(8) जहां बाल न्यायालय यह निर्णय लेता है कि बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की आवश्यकता है:

(i) इसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, जिसमें सत्रों के माध्यम से सुनवाई की जाएगी और बच्चों के अनुकूल माहौल बनाए रखा जाएगा।

(ii) बाल न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश में आवश्यक रूप से बच्चे के लिए प्रपत्र 7 के अनुसार एक व्यक्तिगत देखभाल योजना शामिल होगी, जिसे परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन द्वारा, जहां संभव हो, बच्चे और उसके परिवार के साथ बातचीत के आधार पर तैयार किया जाएगा।

(iii) जहां बच्चा अपराध में संलिप्त पाया जाता है, वहां बच्चे को इक्कीस वर्ष की आयु तक सुरक्षित स्थान पर भेजा जा सकता है।

(iv) जब तक बच्चा सुरक्षित स्थान पर रहेगा, प्रोबेशन अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा फॉर्म 13 में बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए वार्षिक समीक्षा की जाएगी और रिपोर्ट बाल न्यायालय को भेजी जाएगी।

(v) बाल न्यायालय बच्चे को समय-समय पर तथा कम से कम प्रत्येक तीन माह में एक बार अपने समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश भी दे सकता है, ताकि बच्चे द्वारा की गई प्रगति तथा व्यक्तिगत देखभाल योजना के कार्यान्वयन के लिए संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का आकलन किया जा सके।

(vi) जब बच्चा इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है और अभी तक रहने की अवधि पूरी नहीं हुई है, तो बाल न्यायालय:

(क) बच्चे के साथ बातचीत करें ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि क्या बच्चे में सुधारात्मक परिवर्तन हुए हैं और क्या बच्चा समाज का योगदान देने वाला सदस्य बन सकता है।

(ख) यदि आवश्यक हो तो परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या किसी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा तैयार की गई बच्चे की प्रगति की आवधिक रिपोर्टों को ध्यान में रखें और यदि संस्थागत तंत्र अपर्याप्त हो तो उसे मजबूत करने का निर्देश दें।

(ग) से (गड) xx xx

(vii) xx xx"

यौन अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रासंगिक प्रावधान का उद्धरण

"धारा 28. विशेष न्यायालयों की नियुक्ति—

(1) त्वरित सुनवाई प्रदान करने के उद्देश्यों के लिए, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र न्यायालय को अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय के रूप में नामित करेगीः

बशर्ते कि यदि किसी सत्र न्यायालय को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) के तहत बाल न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया जाता है या किसी अन्य कानून के तहत समान उद्देश्यों के लिए नामित विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया जाता है, तो ऐसे न्यायालय को इस धारा के तहत एक विशेष न्यायालय माना जाएगा।

(2) इस अधिनियम के तहत किसी अपराध का मुकदमा चलाते समय, एक विशेष न्यायालय एक ऐसे अपराध का भी मुकदमा चलाएगा, जिसके लिए अभियुक्त पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के तहत उसी मुकदमे में आरोप लगाया जा सकता है।

(3) इस अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय को, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में किसी बात के होते हुए भी, उस अधिनियम की धारा 67 बी के तहत अपराधों पर विचार करने का अधिकार होगा, जहां तक यह किसी भी कार्य, आचरण या तरीके से बच्चों को चित्रित करने वाली यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण से संबंधित है या बच्चों के ऑनलाइन दुरुपयोग की सुविधा प्रदान करता है।

II. **<u>क्या अधिनियम की धारा 14(3) के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन पूरा करने के लिए प्रदान की गई अवधि अनिवार्य है या निर्देशात्मक।</u>**

9. अधिनियम की धारा 15 बोर्ड को जघन्य अपराधों का प्रारंभिक मूल्यांकन करने में सक्षम बनाती है, जहां ऐसा अपराध 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे द्वारा किया गया है। प्रारंभिक मूल्यांकन ऐसे अपराध को करने की उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता और जिन परिस्थितियों में अपराध कथित रूप से किया गया था, उनके संबंध में किया जाना है। उक्त धारा के प्रावधान में यह प्रावधान है कि ऐसा मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड किसी अनुभवी मनोवैज्ञानिक या मनो-सामाजिक कार्यकर्ता या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है। इसके स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि प्रारंभिक मूल्यांकन की प्रक्रिया एक परीक्षण नहीं है, बल्कि केवल ऐसे बच्चे की कथित अपराध करने और उसके परिणामों को समझने की क्षमता का आकलन करना है। विशेषज्ञ की सहायता का महत्व अधिनियम की धारा 101(2) से भी स्पष्ट है। धारा 15 के तहत पारित आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते समय अपीलीय प्राधिकारी बोर्ड की सहायता करने वाले विशेषज्ञों के अलावा अन्य विशेषज्ञों की सहायता भी ले सकता है।

9.1 इस न्यायालय द्वारा **बरुन चंद्र ठाकुर के मामले (सुप्रा)** में उक्त प्रावधान के महत्व पर विचार किया गया था, जहां ऐसी सहायता की आवश्यकता को अनिवार्य माना गया था, भले ही अधिनियम की धारा 15(1) और धारा 101(2) के प्रावधान में प्रयुक्त शब्द 'हो सकता है' हैं।

9.2 अधिनियम की धारा 14(3) में प्रावधान है कि धारा 15 के संदर्भ में प्रारंभिक मूल्यांकन बोर्ड द्वारा बोर्ड के समक्ष बच्चे के पहले जन्म की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है।

9.3 यदि अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सी.सी.एल. का परीक्षण एक वयस्क के रूप में किया जाना है, तो बोर्ड अभिलेखों को अधिकार क्षेत्र वाले बाल न्यायालय को हस्तांतरित करेगा।

9.4 अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क यह था कि सी.सी.एल. 03.11.2021 को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 02.02.2022 को तीन महीने की अवधि समाप्त हो गई है, उसके बाद बोर्ड द्वारा पारित कोई भी आदेश अमान्य है, और सी.सी.एल. का परीक्षण अब बाल न्यायालय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

9.5 हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या धारा 14 के तहत परिकल्पित जांच के समापन के लिए समय सीमा अनिवार्य है या निर्देशिका?

9.6 अधिनियम की धारा 14 की योजना के अनुसार, इसकी उप-धारा (1) में प्रावधान है कि जब बोर्ड के समक्ष एक सी.सी.एल. पेश किया जाता है, तो जांच करने के बाद, वह ऐसे सी.सी.एल. के संबंध में आदेश पारित कर सकता है जो वह अधिनियम की धारा 17 और 18 के तहत उचित समझता है।

9.7 अधिनियम की धारा 17 में ऐसे बच्चे के संबंध में आदेश की परिकल्पना की गई है जो कानून का उल्लंघन नहीं करता पाया गया है। जबकि धारा 18 (1) में ऐसे बच्चे के मामले में पारित आदेश की परिकल्पना की गई है जो कानून का उल्लंघन करता पाया गया हो। इसमें 16 वर्ष या उससे अधिक आयु का बच्चा शामिल है जो किसी जघन्य अपराध में शामिल है, लेकिन बोर्ड द्वारा जांच की जानी है।

9.8 अधिनियम की धारा 14(2) में यह प्रावधान है कि धारा 14(1) के तहत परिकल्पित जांच, बोर्ड के समक्ष बच्चे को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। बोर्ड द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों से समय को अधिकतम दो महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधिनियम की धारा 14(4) में केवल छोटे अपराधों के संदर्भ में ऐसी किसी जांच के निष्फल होने के परिणामों का प्रावधान किया

गया है। उपर्युक्त उप-धारा में यह प्रावधान है कि यदि छोटे अपराधों के लिए उप-धारा (2) के तहत बोर्ड द्वारा की गई जांच विस्तारित अवधि के बाद भी अधूरी रहती है, तो कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी। उपर्युक्त उप-धारा के प्रावधान में यह प्रावधान है कि यदि बोर्ड को गंभीर और जघन्य अपराधों की जांच पूरी करने के लिए समय के और विस्तार की आवश्यकता होती है, तो इसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या, जैसा भी मामला हो, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से प्रदान किया जाएगा।

9.9 इसका अर्थ यह है कि जहां तक अधिनियम की धारा 14(1) के तहत जघन्य अपराधों के लिए बोर्ड द्वारा सीसीएल की जांच का संबंध है, ऐसी कोई समय सीमा नहीं है जिसके बाद जांच आगे नहीं बढ़ाई जा सकती या उसे समाप्त करना पड़ता है।

9.10 अब मुद्दे की बात करें। इसमें कोई विवाद नहीं है कि सी.सी.एल. ने कथित रूप से जघन्य अपराध किया है। यह तर्क अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन के समापन और अधिनियम की धारा 15(2) या 18(3) के तहत आदेश पारित करने के लिए प्रदान की गई अवधि के संदर्भ में है, अर्थात क्या मामले की जांच बोर्ड द्वारा की जानी है या सी.सी.एल. के वयस्क के रूप में सुनवाई के लिए बाल न्यायालय को स्थानांतरित किया जाना है।

9.11 हम यहां यह जोड़ सकते हैं कि धारा 18(3) का स्थान स्पष्ट रूप से उचित नहीं लगता है। धारा 18 की उप-धारा (1) और (2) सीसीएल के खिलाफ जांच पर बोर्ड द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेशों से संबंधित हैं, जबकि उप-धारा (3) बोर्ड द्वारा आदेश पारित करने की परिकल्पना करती है कि क्या सीसीएल का परीक्षण प्रारंभिक मूल्यांकन के संदर्भ में बाल न्यायालय द्वारा किया जाना है, जैसा कि धारा 15 में परिकल्पित है। इस तरह के आदेश को धारा 15 में ही उप-धारा (2) के बाद रखा जा सकता है।

9.12 अधिनियम की धारा 15(1) में परिकल्पित जांच बोर्ड को अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या मनोवैज्ञानिक सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों से सहायता लेने में

सक्षम बनाती है। प्रावधान का उद्देश्य प्राप्त करने के साथ संबंध है। अधिनियम सीसीएल से संबंधित है। धारा 15 में परिकल्पित प्रारंभिक मूल्यांकन के बड़े निहितार्थ हैं, अर्थात्, क्या सीसीएल के खिलाफ जांच बोर्ड द्वारा की जानी है, जहां अंतिम सजा, जो दी जा सकती है वह हल्की है या सुनवाई बच्चों के न्यायालय द्वारा सीसीएल को एक वयस्क के रूप में मानते हुए की जानी है, जहां सजा कठोर हो सकती है।

9.13 जैसा कि पहले देखा गया है, अधिनियम की धारा 15(1) के संदर्भ में बोर्ड द्वारा जघन्य अपराध का प्रारंभिक मूल्यांकन अधिनियम की धारा 14(3) के संदर्भ में तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाना है। अधिनियम में समय के किसी भी विस्तार का प्रावधान नहीं है और अनुमेय समय के भीतर जांच का संकलन न करने के परिणाम को भी निर्धारित नहीं किया गया है। इसके अभाव में जांच पूरी करने की समय सीमा निर्धारित करने वाले प्रावधान को अनिवार्य नहीं माना जा सकता है। गंभीर या जघन्य अपराधों के संदर्भ में विधायिका का इरादा अधिनियम की धारा 14 की भाषा से भी उपलब्ध है जो स्वयं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए बोर्ड द्वारा जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने का प्रावधान करता है। यह दो महीने के विस्तार के अलावा है जिसे बोर्ड स्वयं दे सकता है।

9.14 चूंकि प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया में कई व्यक्ति शामिल होते हैं, जैसे जांच अधिकारी, विशेषज्ञ जिनकी राय ली जानी है और उसके बाद बोर्ड के समक्ष कार्यवाही, जहां विभिन्न कारणों से कोई भी पक्ष कार्यवाही में देरी कर सकता है, हमारी राय में धारा 14(3) में दिए गए समय को अनिवार्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें विफलता के कोई परिणाम नहीं दिए गए हैं, जैसा कि अधिनियम की धारा 14(4) के अनुसार छोटे अपराधों की जांच के मामले में है। यदि हम मामले के तथ्यों को देखें, तो जांच अधिकारी ने निमहंस से रिपोर्ट प्राप्त करने में लगभग दो महीने का समय लिया था।

9.15 जहाँ किसी क़ानून में निर्धारित अवधि के लिए चूक के परिणामों का उल्लेख नहीं किया गया है, वहाँ उन्हें अनिवार्य नहीं माना जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए, इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता है।

9.16 इस न्यायालय ने **टॉपलाइन शूज लिमिटेड बनाम कॉरपोरेशन बैंक**[17] मामले में निरस्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 13(2)(ए) की व्याख्या करते हुए शिकायत पर जवाब दाखिल करने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी, इसे निर्देशिका प्रकृति का माना। इसका प्रासंगिक पैरा 11 नीचे उद्धृत किया गया है:

> "11. हम पहले ही देख चुके हैं कि धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (ए) के अंतर्गत निहित प्रावधान प्रक्रियात्मक प्रकृति का है। यह भी स्पष्ट है कि अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ताकि ऐसे मामलों का त्वरित निपटान हो सके, यह प्रावधान किया गया है कि जवाब 30 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना है और समय का विस्तार 15 दिनों से अधिक नहीं हो सकता है। इस प्रावधान में यह परिकल्पना की गई है कि विरोधी पक्ष द्वारा अपना जवाब दाखिल किए बिना कार्यवाही बहुत लंबे समय तक नहीं बढ़ाई जा सकती है। <u>हालांकि, समय विस्तार 15 दिनों से अधिक होने की स्थिति में कोई दंडात्मक परिणाम प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता के पक्ष में कोई मूल अधिकार अर्जित हुआ है या विस्तारित समय के भीतर जवाब दाखिल करने में किसी प्रकार की सीमा का प्रतिबंध था, भले ही कुल मिलाकर 45 दिन से अधिक हो।</u> उत्तर को अस्वीकार करना आवश्यक नहीं है। मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण यह भी

[17] (2002) 6 एससीसी 33: 2002 आईएनएससी 287: (2002) 3 एससीआर 1167

प्रावधान करता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

(जोर दिया गया)

9.17 इस न्यायालय ने **कैलाश बनाम नन्हकू एवं अन्य**[18] मामले में आदेश VIII नियम 1 सीपीसी की व्याख्या करते हुए लिखित बयान दाखिल करने की समय सीमा निर्धारित की थी, इसे निर्देशिका प्रकृति का माना था। इसके प्रासंगिक पैरा 30 और 46 नीचे उद्धृत किए गए हैं:

"30. <u>यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि नियम 1 आदेश 8 में संलग्न प्रावधान के तहत न्यायालय की शक्ति "नब्बे दिन से अधिक नहीं होगी" शब्दों द्वारा परिबद्ध है, लेकिन समय के गैर-विस्तार से होने वाले परिणामों के लिए विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया गया है, हालांकि उन्हें आवश्यक निहितार्थ द्वारा पढ़ा जा सकता है।</u> केवल इसलिए कि कानून का प्रावधान अनिवार्य चरित्र को दर्शाते हुए नकारात्मक भाषा में लिखा गया है, यह अपवादों के बिना नहीं है। जब न्यायालयों को प्रावधान की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है, तो वे उस पूरे संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, जिसमें प्रावधान अधिनियमित हुआ था, इसे नकारात्मक रूप में शब्दबद्ध होने के बावजूद निर्देशिका मान सकते हैं।

x x x

46. हम अपने निष्कर्षों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं:

(i) - (iii) xxxx

(iv) आदेश 8 नियम 1 सीपीसी के तहत लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय अनुसूची प्रदान करने का उद्देश्य सुनवाई में तेजी लाना है, न कि

[18] (2005) 4 एससीसी 480: 2005 आईएनएससी 186: (2005) 3 एससीआर 289

उसे बाधित करना। प्रावधान प्रतिवादी पर एक अक्षमता को स्पष्ट करता है। यह समय बढ़ाने के लिए न्यायालय की शक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। यद्यपि नियम 1 आदेश 8 सीपीसी के प्रावधान की भाषा नकारात्मक रूप में है, यह गैर-अनुपालन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दंडात्मक परिणाम को निर्दिष्ट नहीं करता है। प्रावधान प्रक्रियात्मक कानून के क्षेत्र में होने के कारण इसे निर्देशिका माना जाना चाहिए न कि अनिवार्य। आदेश 8 नियम 1 सीपीसी द्वारा प्रदान की गई समय-सीमा से परे लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की न्यायालय की शक्ति पूरी तरह से छीनी नहीं गई है।

(v) हालांकि आदेश 8 नियम 1 सीपीसी प्रक्रियात्मक कानून का एक हिस्सा है और इसलिए निर्देशात्मक है, नागरिक मामलों के शीघ्र परीक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिसने संसद को अपने वर्तमान स्वरूप में प्रावधान को अधिनियमित करने के लिए राजी किया, यह माना जाता है कि आमतौर पर प्रावधान में निहित समय सारिणी का एक नियम के रूप में पालन किया जाना चाहिए और इससे विचलन अपवाद के रूप में होगा। प्रतिवादी द्वारा समय के विस्तार के लिए की गई प्रार्थना को केवल नियमित रूप से और केवल पूछने पर ही नहीं दिया जाएगा, खासकर तब जब 90 दिनों की अवधि समाप्त हो गई हो। प्रतिवादी द्वारा निर्दिष्ट कारणों के लिए अपवाद के रूप में समय का विस्तार दिया जा सकता है और अदालत द्वारा संतुष्ट होने पर इसे लिखित रूप में रिकॉर्ड में भी रखा जा सकता है, चाहे वह कितना भी संक्षिप्त क्यों न हो। समय विस्तार की अनुमति दी जा सकती है यदि यह उन परिस्थितियों के लिए दिया जाना आवश्यक है जो असाधारण हैं, प्रतिवादी के नियंत्रण से परे कारणों से उत्पन्न हुई हैं और यदि समय नहीं बढ़ाया गया तो गंभीर अन्याय होगा। किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के

आधार पर, प्रतिवादी द्वारा समय विस्तार के लिए दिए गए आधारों के समर्थन में लागत लगाई जा सकती है और हलफनामा या दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।"

(जोर दिया गया)

9.18 इस न्यायालय ने **बिहार राज्य एवं अन्य बनाम बिहार राज्य भूमि विकास बैंक समिति**[19] में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (5) एवं (6) के तहत उपधारा (6) में निर्धारित अवधि को निर्देशिका माना है। प्रासंगिक पैरा 23, 25 एवं 26 नीचे उद्धृत हैं:

"23. इस प्रावधान से यह देखा जा सकता है कि धारा 34(5) और (6) के विपरीत, यदि कोई निर्णय धारा में निहित निर्धारित या विस्तारित अवधि से परे किया जाता है, तो मध्यस्थ के जनादेश को समाप्त करने का परिणाम स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाता है। यह प्रावधान धारा 34(5) और (6) के बिल्कुल विपरीत है, जहां जैसा कि ऊपर कहा गया है, यदि धारा 34 के तहत आवेदन पर निर्णय लेने की अवधि बीत गई है, तो कोई परिणाम प्रदान नहीं किया गया है। यह एक और संकेत है कि एक ही संशोधन अधिनियम ने, जब विभिन्न स्थितियों में समय अवधि प्रदान की, तो ऐसा अलग-अलग परिणामों के इरादे से किया।

x x x

25. अब हम उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों पर आते हैं। पटना उच्च न्यायालय बिहार राज्य भूमि विकास बैंक समिति बनाम बिहार राज्य, 2016 एससीसी ऑनलाइन पट 10104, केरल [शम्सुद्दीन बनाम श्रीराम ट्रांसपोर्ट

[19] (2018) 9 एससीसी 472: 2018 आईएनएससी 648: (2018) 7 एससीआर 1147

फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, 2016 एससीसी ऑनलाइन केर 23728], हिमाचल प्रदेश [माधव हाईटेक इंजीनियर्स (पी) लिमिटेड बनाम कार्यकारी अभियंता, 2017 एससीसी ऑनलाइन एचपी 2212], दिल्ली [मशीन टूल इंडिया लिमिटेड बनाम स्प्लेंडर बिल्डवेल (पी) लिमिटेड, 2018 एससीसी ऑनलाइन डेल 9551], और गुवाहाटी [यूनियन ऑफ इंडिया बनाम दुर्गा कृष्ण स्टोर (पी) लिमिटेड, 2018 एससीसी ऑनलाइन गौ 907] सभी ने यह विचार किया है कि धारा 34(5) प्रकृति में अनिवार्य है। जिस बात पर दृढ़ता से भरोसा किया गया है, वह है प्रावधान द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य और धारा 34(5) में प्रयुक्त भाषा की अनिवार्य प्रकृति। समान रूप से, समान परिणाम तक पहुँचने के लिए धारा 80 सीपीसी के साथ समानताएँ खींची गई हैं। दूसरी ओर, ग्लोबल एविएशन सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया [ग्लोबल एविएशन सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 2018 एससीसी ऑनलाइन बॉम 233] में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने द्वारा पूछे गए प्रश्न 4 का उत्तर देते हुए, हमारे कुछ निर्णयों का अनुसरण करते हुए माना कि प्रावधान निर्देशिका है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि निर्दिष्ट समय-सीमा के उल्लंघन के लिए कोई परिणाम प्रदान नहीं किया गया है। जब इस तर्क का सामना किया गया कि प्रावधान का उद्देश्य निरर्थक हो जाएगा यदि इसे निर्देशिका के रूप में समझा जाए, तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित माना: (एससीसी ऑनलाइन बॉम पैरा 133)

> "133. जहाँ तक प्रतिवादी के विद्वान वकील के इस तर्क का सवाल है कि यदि धारा 34(5) को निर्देशात्मक माना जाता है, तो संशोधनों का पूरा उद्देश्य निरर्थक हो जाएगा, मेरे विचार में, प्रतिवादी के विद्वान

वकील द्वारा दिए गए इस तर्क में कोई दम नहीं है। चूँकि उक्त प्रावधान में इसके गैर-अनुपालन की स्थिति में कोई परिणाम प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए उक्त प्रावधान को अनिवार्य नहीं माना जा सकता। मामले को तेजी से आगे बढ़ाने में किसी भी देरी से बचने का उद्देश्य बॉम्बे उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमों में उचित नियम को शामिल करके पहले ही पूरा किया जा चुका है। न्यायालय हमेशा याचिकाकर्ता को यह निर्देश दे सकता है कि वह मामले को स्वीकार करने और अंतिम सुनवाई के लिए न्यायालय द्वारा सुनवाई से पहले अन्य पक्ष को कागजात और कार्यवाही के साथ नोटिस जारी करे। मध्यस्थता याचिका दायर करने से पहले पूर्व नोटिस जारी करने के गैर-अनुपालन के लिए धारा 34 के तहत किसी पुरस्कार को चुनौती देने के किसी पक्ष के निहित अधिकारों को नहीं छीना जा सकता है।"

उपरोक्त निर्णय के बाद बॉम्बे [महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड बनाम सिम्प्लेक्स गायत्री कंसोर्टियम, 2018 एससीसी ऑनलाइन बॉम 805] और कलकत्ता [श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड बनाम कैंडोर गुड़गांव टू डेवलपर्स एंड प्रोजेक्ट्स (पी) लिमिटेड, 2018 एससीसी ऑनलाइन कैल 5606] के उच्च न्यायालयों के हाल के निर्णय आए हैं।

26. हमारा मानना है कि बॉम्बे और कलकत्ता उच्च न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण कानून की सही स्थिति को दर्शाता है। हालांकि, हम यह भी जोड़ सकते हैं कि प्रत्येक न्यायालय का यह प्रयास होगा कि जिसमें धारा 34 के तहत आवेदन दायर किया गया है, वह आवेदक या न्यायालय द्वारा, जैसा भी मामला हो, विपरीत पक्ष को नोटिस की सेवा की तारीख से एक वर्ष की समय-सीमा का पालन करे। यदि न्यायालय धारा 34(3) में उल्लिखित अवधि

बीत जाने के बाद नोटिस जारी करता है, तो प्रत्येक न्यायालय उक्त आवेदन के दाखिल होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर धारा 34 के तहत आवेदन का निपटान करने का प्रयास करेगा, जैसा कि वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग अधिनियम, 2015 की धारा 14 में प्रदान किया गया है। यह 2015 संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 13(6) को जोड़कर प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को प्रभावी करेगा।"

(जोर दिया गया)

9.19 **सी. ब्राइट बनाम डिस्ट्रिक्ट एवं अन्य**[20] में इस न्यायालय ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 की प्रकृति की व्याख्या करते हुए निर्धारित अवधि को, जिसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 30 दिनों के भीतर सुरक्षित आस्तियों का कब्जा सौंपना अनिवार्य है, जिसे कुल 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, प्रकृति में निर्देशिका माना। प्रासंगिक पैरा 8 और 11 नीचे उद्धृत किए गए हैं:

"8. विधियों की व्याख्या का एक सुस्थापित नियम यह है कि किसी विधि में "करेगा" शब्द का प्रयोग, जरूरी नहीं कि हर मामले में यह अनिवार्य हो कि जब तक विधि के शब्दों का अक्षरशः पालन न किया जाए, कार्यवाही या कार्यवाही का परिणाम अमान्य होगा। यह कहना हमेशा सही नहीं होता कि यदि "कर सकता है" शब्द का प्रयोग किया गया है, तो विधि केवल इस अर्थ में अनुमेय या निर्देशात्मक है कि उन प्रावधानों का पालन न करने से कार्यवाही अमान्य नहीं होगी [यू.पी. राज्य बनाम मनबोधन लाल श्रीवास्तव, एआईआर 1957 एससी 912] और जब कोई विधि "करेगा" शब्द का प्रयोग

[20] (2021) 2 एससीसी 392: 2020 आईएनएससी 633: (2020) 7 एससीआर 997

करती है, तो प्रथम दृष्टया यह अनिवार्य है, लेकिन न्यायालय विधि के संपूर्ण दायरे पर ध्यानपूर्वक ध्यान देकर विधायिका के वास्तविक इरादे का पता लगा सकता है [यू.पी. राज्य बनाम मनबोधन लाल श्रीवास्तव, एआईआर 1957 एससी 912] बनाम बाबू राम उपाध्याय, एआईआर 1961 एससी 751]। क़ानून के संदर्भ और योजना की जांच किए बिना सभी परिस्थितियों में क़ानून के शाब्दिक निर्माण का सिद्धांत क़ानून के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता है [आरबीआई बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, (1987) 1 एससीसी 424]

x x x

11. <u>रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम वर्कमेन [रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम वर्कमेन, एआईआर 1968 एससी 224] के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17 पर विचार किया गया। उठाया गया तर्क यह था कि श्रम न्यायालय द्वारा पंचाट के प्रकाशन की 30 दिनों की समय-सीमा अनिवार्य है। इस न्यायालय ने माना कि यद्यपि धारा 17 अनिवार्य है, लेकिन 30 दिनों के भीतर पंचाट प्रकाशित करने की समय-सीमा अन्य बातों के साथ-साथ इस कारण से भी निर्देशिका है कि तीस दिनों की अवधि के भीतर पंचाट का प्रकाशन न करने पर कोई दंड नहीं लगता है।</u>"

(जोर दिया गया)

9.20 उपर्युक्त के विपरीत, जहां कानून में किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए निर्धारित अवधि के भीतर गैर-अनुपालन के परिणामों का उल्लेख किया गया है, वही इस न्यायालय द्वारा **एससीजी कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम के.एस. चमनकर**

इंफ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड[21] में अनिवार्य माना गया था। यह उच्च न्यायालय अधिनियम, 2015 के वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग के संदर्भ में वाणिज्यिक विवादों से संबंधित मुकदमों के लिए संशोधित सीपीसी के आदेश VIII नियम 1 के संदर्भ में था। निर्णय के प्रासंगिक पैरा नीचे उद्धृत किए गए हैं:

> "10. संशोधित आदेश 8 नियम 1 पर कई उच्च न्यायालय के निर्णयों ने अब माना है कि लिखित बयान दाखिल न करने के परिणाम को देखते हुए, सीपीसी के संशोधित प्रावधानों को अनिवार्य माना जाना चाहिए। ओकू टेक (पी) लिमिटेड बनाम संगीत अग्रवाल, 2016 एससीसी ऑनलाइन डेल 6601 को दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 11-8-2016 को सीएस (ओएस) संख्या 3390/2015 में पारित किया गया, जिसके बाद कई अन्य निर्णय दिए गए, जिनमें माजा कॉस्मेटिक्स बनाम ओएसिस कमर्शियल (पी) लिमिटेड, 2018 एससीसी ऑनलाइन डेल 6698 में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय भी शामिल है।
>
> 11. हमारा मानना है कि इन निर्णयों में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है, क्योंकि लिखित बयान दाखिल करने के अधिकार को जब्त करने का परिणाम; किसी भी अतिरिक्त समय का विस्तार न करना; और यह तथ्य कि न्यायालय लिखित बयान को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति नहीं देगा, ये सभी इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि आदेश 8 नियम 1 के तहत लिखित बयान दाखिल करने पर आदेश 8 नियम 1 पर पहले का कानून अब रद्द कर दिया गया है।"

(जोर दिया गया)

---

[21] (2019) 12 एससीसी 210: 2019 आईएनएससी 187: (2019) 3 एससीआर 1050

9.21 **बरुण चंद्र ठाकुर के मामले (ऊपर)** में इस न्यायालय का निर्णय अपीलार्थी के बचाव में नहीं आता है। इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में केवल अनुच्छेद 59 और 60 में अधिनियम की योजना पर ध्यान दिया था और निष्कर्ष निकाला था कि अधिनियम के तहत जांच और परीक्षणों का समापन शीघ्र होना चाहिए, यह अधिनियम की योजना है।

9.22 इसलिए, हमारा मानना है कि जांच करने के लिए अधिनियम की धारा 14(2) में दिया गया समय अनिवार्य नहीं है, बल्कि निर्देशात्मक है। धारा 14(3) में दिया गया समय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से बढ़ाया जा सकता है।

9.23 यह मानते हुए कि प्रारंभिक मूल्यांकन पूरा करने के लिए धारा 14(3) के तहत प्रदान की गई अवधि अनिवार्य नहीं है, आगे क्या? हम स्थिति को और स्पष्ट करना अपना कर्तव्य समझते हैं। इस उद्देश्य के लिए, **एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य बनाम चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य**[22] में इस्तेमाल किए गए व्याख्या के साधनों का उपयोग स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त रूप से किया जा सकता है। उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय के समक्ष विचार धारा 89 सीपीसी की व्याख्या थी। (देखें: पैराग्राफ 20 और 21)

9.24 व्याख्या के सख्त नियम में परिनियम से अनुपबन्दित विषय (कॉसस ओमिसस) का नियम यानी 'जो क़ानून में नहीं दिया गया है, उसे अदालतें नहीं दे सकतीं'। हालाँकि, इसके कुछ अपवाद भी हैं। **सुरजीत सिंह कालरा बनाम भारत संघ और अन्य**[23] में इस न्यायालय के निर्णय का पैरा '19' इस पर प्रकाश डालता है। नीचे उसी का उद्धरण दिया गया है:

> "19. सच है कि किसी क़ानून में ऐसे शब्दों को पढ़ना जायज़ नहीं है जो वहाँ मौजूद ही नहीं हैं, लेकिन "<u>जहाँ विकल्प या तो निहितार्थ के तौर पर ऐसे</u>

[22] (2010) 8 एससीसी 24: 2010 आईएनएससी 431: (2010) 8 एससीआर 1053

[23] (1991) 2 एससीसी 87: 1991 आईएनएससी 36: (1991) 1 एससीआर 364

शब्दों को शामिल करना है जो गलती से छूट गए लगते हैं, या ऐसी संरचना को अपनाना है जो कुछ मौजूदा शब्दों को सभी अर्थों से वंचित कर देती है, वहाँ शब्दों को शामिल करना जायज़ है" (क्रेज़ क़ानून, 7 वाँ संस्करण, पृ.109)। हमीदिया हार्डवेयर स्टोर्स बनाम बी. मोहन लाल सोकार, (1988) 2 एससीसी 513, 524-25 में भी ऐसी ही टिप्पणियाँ की गई हैं जहाँ यह देखा गया कि किसी प्रावधान की व्याख्या करने वाले न्यायालय को उसमें ऐसे शब्दों को आसानी से नहीं पढ़ना चाहिए जो स्पष्ट रूप से अधिनियमित नहीं किए गए हैं, लेकिन उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें प्रावधान दिखाई देता है और क़ानून का उद्देश्य जिसमें उक्त प्रावधान अधिनियमित किया गया है, न्यायालय को इसे सार्थक बनाने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से इसकी व्याख्या करनी चाहिए। प्रासंगिक प्रावधानों को इस तरह से समेटने का प्रयास हमेशा किया जाना चाहिए कि क़ानून द्वारा इच्छित उपाय को आगे बढ़ाया जा सके। (देखें: सिराजुल हक खान बनाम सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ, 1959 एससीआर 1287, 1299: एआईआर 1959 एससी 198)"

(जोर दिया गया)

(जोर दिया गया)

9.25 इसके बाद इस मामले पर इस न्यायालय ने **राजबीर सिंह दलाल (डॉ.) बनाम चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा और अन्य**[24] में विचार किया। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने टिप्पणी की: 'जहां विकल्प या तो निहितार्थ के आधार पर ऐसे शब्दों को शामिल करना है जो गलती से छूट गए प्रतीत होते हैं, या सख्त निर्माण को अपनाना है जो बेतुकापन की ओर ले जाता है या कुछ मौजूदा शब्दों को सभी अर्थों से वंचित करता है, और इस स्थिति में शब्दों को शामिल करना स्वीकार्य है (देखें न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह द्वारा

[24] (2008) 9 एससीसी 284: 2008 आईएनएससी 913: (2008) 11 एससीआर 992

वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, 9वां संस्करण, पृ. 71-76)'। इस न्यायालय ने व्याख्या के पारंपरिक सिद्धांतों पर भी विचार किया जिन्हें 'व्याख्या के मीमांसा नियम' के रूप में जाना जाता है। उपरोक्त मामले में विचाराधीन मुद्दा सार्वजनिक प्रशासन में विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के बारे में था। व्याख्या के साधनों को लागू करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि रीडर के पद के लिए आवश्यक योग्यता में 'स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर' शब्दों के बाद 'प्रासंगिक विषय' जोड़ा जाना चाहिए ताकि नियमों की व्याख्या उद्देश्यपूर्ण ढंग से की जा सके।

9.26 इसी सिद्धांत का पालन इस न्यायालय ने **केंद्रीय जांच ब्यूरो, बैंक प्रतिभूति और धोखाधड़ी प्रकोष्ठ बनाम रमेश गेली और अन्य**[25] में किया था।

9.27 हमारी राय में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को धारा 14(1) के तहत परिकल्पित जांच की अवधि बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (4) से जो मार्गदर्शन स्पष्ट है, वह उप-धारा (3) में परिकल्पित अवधि के विस्तार के लिए भी लागू होगा। इस तरह का विस्तार लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से सीमित अवधि के लिए दिया जा सकता है। समय विस्तार के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय, विशेषज्ञों की राय प्राप्त होने में देरी एक प्रासंगिक कारक होगी। यह अधिनियम की भावना के अनुरूप होगा और इसे एक उद्देश्यपूर्ण अर्थ देगा।

9.28 हम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा **भोला बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[26] और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा **सीसीएल बनाम दिल्ली राज्य (एनसीटी)**[27] में व्यक्त किए गए विचारों को स्वीकार करते हैं, जिन्होंने अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों से निपटते हुए माना है कि प्रारंभिक मूल्यांकन पूरा करने के लिए निर्धारित समय अवधि अनिवार्य नहीं है, बल्कि प्रकृति में केवल निर्देशात्मक है। हम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा **नीरज**

---

[25] (2016) 3 एससीसी 788: 2016 आईएनएससी 134: (2016) 1 एससीआर 762

[26] 2019 एससीसी ऑनलाइन एमपी 521

[27] 2023 एससीसी ऑनलाइन देल 5063

और अन्य बनाम हरियाणा राज्य[28] और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा **एक्स (अपने बड़े भाई के माध्यम से) बनाम राज्य**[29] में व्यक्त किए गए विचारों को भी स्वीकार करते हैं, जिन्होंने निरस्त किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के समरूप प्रावधानों से निपटते हुए भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे।

III. **उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग**

10. वर्तमान अपील में चुनौती के तहत आदेश शिकायतकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था, जिसमें बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 10.04.2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत बोर्ड के समक्ष कार्यवाही समाप्त करने और मामले को सुनवाई के लिए बाल न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए अधिनियम की धारा 19 के तहत उसके द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट द्वारा 05.04.2022 को पारित आदेश अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार अंतिम था, क्योंकि कोई बहुमत की राय नहीं दी जा सकती थी।

10.1 कानून के प्रावधानों के अनुसार, सीसीएल उस आदेश के खिलाफ शिकायत कर सकता था और उसके खिलाफ अपने उपाय का लाभ उठा सकता था, लेकिन कार्यवाही को आगे जारी रखने की अनुमति दी गई। यह जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है कि बोर्ड के दो सदस्यों ने प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी के बिना मामले में अलग दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्यवाही कैसे की। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि जब 12.04.2022 को बोर्ड के दो सदस्यों द्वारा बाद में आदेश पारित किया गया, तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का पहले ही तबादला हो चुका था, जैसा कि उच्च न्यायालय के आदेश (पैरा 19) से स्पष्ट है। वास्तव में, बोर्ड के दो सदस्यों द्वारा 12.04.2022 को पारित आदेश जिसमें बोर्ड द्वारा मामले में जांच का

[28] 2005 एससीसी ऑनलाइन पी&एच 611

[29] 2019 एससीसी ऑनलाइन देल 11164

निर्देश दिया गया था, कानून की नजर में गैर-कानूनी था, अगर अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार सख्ती से विचार किया जाए। बोर्ड द्वारा पारित विभिन्न आदेशों से यह स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी या एपीपी (लोक अभियोजक) या बुलाए गए गवाहों की अनुपस्थिति के कारण जांच आगे नहीं बढ़ सकी। उस स्तर पर, शिकायतकर्ता द्वारा बोर्ड के समक्ष कार्यवाही समाप्त करने और मामले को बाल न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए एक आवेदन दिया गया था, जिस पर अपीलकर्ता द्वारा आपत्तियां दर्ज की गई थीं। बोर्ड ने दिनांक 10.04.2023 के आदेश के तहत आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता के पास दिनांक 12.04.2022 के आदेश के खिलाफ अपील का अधिकार था, जिसका लाभ उठाया जा सकता था और बोर्ड के पास अपने आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त आदेश को शिकायतकर्ता द्वारा धारा 397 के साथ धारा 399 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए पुनरीक्षण याचिका दायर करके उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। उपरोक्त याचिका में पारित आदेश ही इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

10.2 सबसे पहले, मुद्दा उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करने के लिए धारा 397 को धारा 399 के साथ पढ़ा जाना और उस आधार पर इसकी स्थिरता के बारे में है। इस पर कुछ भी निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह याचिका में केवल एक गलत धारा का उल्लेख था। अन्यथा उच्च न्यायालय के पास विषय-वस्तु से निपटने की शक्ति है। अधिनियम की धारा 102 उच्च न्यायालय को बोर्ड या बाल न्यायालय द्वारा किसी भी आदेश या कार्यवाही के संदर्भ में अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाती है। इसलिए, इस आधार पर हमें नहीं लगता कि पुनरीक्षण को खारिज किया जाना चाहिए था।

10.3 अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया एक अन्य तर्क यह था कि दिनांक 12.04.2024 के आदेश के विरुद्ध शिकायतकर्ता के पास अपील का उपाय उपलब्ध था, जिसके तहत बोर्ड के दो सदस्यों ने बोर्ड द्वारा सीसीएल द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध

की जांच का निर्देश दिया था। हमारी राय में, भले ही ऐसा उपाय शिकायतकर्ता के लिए उपलब्ध हो सकता है, जिसका सामान्य रूप से लाभ उठाया जाना चाहिए, लेकिन मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि 05.04.2022 को प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक पूर्व आदेश था, जो बाल न्यायालय द्वारा सीसीएल के मुकदमे के संचालन के संबंध में अंतिम था, फिर भी बाद में बोर्ड के दो सदस्यों ने प्रधान मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के बिना 12.04.2022 को बोर्ड द्वारा अपराध की जांच का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया। वास्तव में, बाद का आदेश पूरी तरह से गैर-अनुमानित था। यदि ऐसी स्थिति में भी अपील का उपाय अपनाकर उपरोक्त आदेश को चुनौती नहीं दी गई, तो भी हमारी राय में अधिनियम की धारा 102 के तहत पुनरीक्षण को अस्वीकार्य नहीं कहा जा सकता।

10.4 सबसे पहले, इसमें पुनरीक्षण दाखिल करने के लिए कोई समय सीमा प्रदान नहीं की गई है, और दूसरी बात यह कि यह किसी भी पक्ष द्वारा दायर आवेदन पर हो सकता है। उच्च न्यायालय किसी भी ऐसे आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे। दिनांक 12.04.2022 के आदेश की वैधता के अलावा, यह मामला ऐसा है जहां कार्यवाही का औचित्य भी सवालों के घेरे में था। अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार दिनांक 05.04.2022 के आदेश के पारित होने के बाद बोर्ड के समक्ष कार्यवाही जारी नहीं रह सकती थी।

10.5 इसलिए, ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता द्वारा अपील के उपाय का लाभ न उठाना घातक नहीं माना जा सकता। हम यहां यह भी जोड़ सकते हैं कि अपीलकर्ता भी 05.04.2022 के आदेश के खिलाफ अपील के उपाय का लाभ उठा सकता था, लेकिन उसने बोर्ड के समक्ष गैर-स्थायी कार्यवाही जारी रखने के बारे में सोचा।

IV **किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 101 में विसंगति**

(क) 'बाल न्यायालय' और 'सत्र न्यायालय' जैसे शब्दों के संबंध में

11. अधिनियम की धारा 101 में विभिन्न आदेशों के विरुद्ध अपील का प्रावधान है। इसकी उपधारा (1) में प्रावधान है कि अधिनियम के तहत समिति या बोर्ड द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर बाल न्यायालय में अपील कर सकता है, इस अपवाद के साथ कि पालन-पोषण देखभाल और प्रायोजन देखभाल से संबंधित समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष की जा सकेगी। अधिनियम की धारा 2(22) में 'समिति' शब्द को धारा 27 के तहत गठित 'बाल कल्याण समिति' के रूप में परिभाषित किया गया है।

धारा 101 की उप-धारा (1) के परंतुक में यह प्रावधान है कि सत्र न्यायालय या जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, दायर करने में देरी के लिए पर्याप्त कारण दिखाए जाने की स्थिति में 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद अपील पर विचार कर सकता है।

11.1 धारा 101 की उपधारा (2) में यह प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन करने के बाद बोर्ड द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील सत्र न्यायालय के समक्ष होगी। अपील पर निर्णय करते समय न्यायालय अनुभवी मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है, उनके अलावा जिनकी सहायता बोर्ड ने विवादित आदेश पारित करते समय ली थी। यह मुद्दे की स्वतंत्र जांच को दर्शाता है। उपधारा (4) में यह प्रावधान है कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ कोई दूसरी अपील नहीं चल पाएगी। **बरुन चंद्र ठाकुर के मामले (सुप्रा)** में प्रावधानों को अनिवार्य माना गया है।

11.2 उपरोक्त परंतुक में कुछ विसंगतियां स्पष्ट हैं, जैसा कि सुनवाई के समय पक्षों के विद्वान वकील ने बताया था। उनका तर्क था कि विसंगतियों को भी दूर किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके। हम भी कानून की भावना को ध्यान में रखते हुए उसी दिशा में सोचते हैं।

11.3 अधिनियम में सत्र न्यायालय शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के सीसीएल का मुकदमा, जो किसी जघन्य अपराध में शामिल है, उसे वयस्क मानते हुए बाल न्यायालय द्वारा चलाया जाना है।

11.4 अधिनियम की धारा 2(20) में 'बाल न्यायालय' की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि इसका अर्थ है 2005 अधिनियम के तहत स्थापित न्यायालय या 2012 अधिनियम के तहत स्थापित विशेष न्यायालय। जहां ऐसे न्यायालय नहीं हैं, वहां सत्र न्यायालय को अधिनियम के तहत अपराध की सुनवाई करने का अधिकार होगा। इसका अर्थ यह है कि बाल न्यायालय और सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को एक ही श्रेणी में रखा गया है। इस प्रस्ताव में कोई संदेह नहीं है कि सत्र न्यायाधीश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी शामिल होंगे।

11.5 2005 अधिनियम की धारा 25 में प्रावधान है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों या बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से अधिसूचना द्वारा राज्य में कम से कम एक न्यायालय या प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र न्यायालय को बाल न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करेगी। इसका अर्थ यह है कि 2005 अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय सत्र न्यायालय के स्तर का है।

11.6 अधिनियम की धारा 101(1) बोर्ड या समिति द्वारा पारित कुछ आदेशों के विरुद्ध बाल न्यायालय में अपील दायर करने से संबंधित है। उपर्युक्त उपधारा के प्रावधान में यह प्रावधान है कि यदि अपील दायर करने में कोई देरी होती है, तो क्षमा करने की शक्ति सत्र न्यायालय में निहित है। 'बाल न्यायालय' शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, हालांकि बाल न्यायालय के समक्ष अपील स्वीकार्य है।

11.7 अधिनियम की धारा 101 की उपधारा (2) में अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान है। अपीलीय प्राधिकारी सत्र न्यायालय बताया गया है।

11.8 2016 के नियमों का नियम 13 बाल न्यायालय और निगरानी प्राधिकरणों के संबंध में प्रक्रिया से संबंधित है। इसके उप-नियम (3) और (4) जो अधिनियम की धारा 101(2) के तहत दायर अपील से संबंधित हैं, अपीलीय प्राधिकरण को 'बाल न्यायालय' के रूप में संदर्भित करते हैं, हालांकि अधिनियम की धारा 101(2) में अपील को सत्र न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य बताया गया है। उपरोक्त प्रावधान से भी यह स्पष्ट है कि 'सत्र न्यायालय' और 'बाल न्यायालय' शब्दों का परस्पर उपयोग किया गया है।

12. अधिनियम की धारा 102 उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण शक्ति प्रदान करती है। यह फिर से किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड को मंगाने की बात करता है जिसमें एक समिति या बोर्ड या बाल न्यायालय या न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया है। यह सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग की बात नहीं करता है। रिकॉर्ड को सीधे तौर पर रखने के लिए, यह जोड़ा गया है कि अधिनियम की धारा 2(23) में 'न्यायालय' शब्द को एक सिविल न्यायालय के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके पास गोद लेने और संरक्षकता के मामलों में अधिकार क्षेत्र है और इसमें जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय और शहर के सिविल न्यायालय शामिल हो सकते हैं।

12.1 इसी तरह, उप-धारा (2) में प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद बोर्ड द्वारा पारित आदेश के खिलाफ, अपील सत्र न्यायालय के समक्ष विचारणीय है। बोर्ड की अध्यक्षता प्रधान मजिस्ट्रेट करते हैं। यहाँ बाल न्यायालय शब्द का उल्लेख नहीं है।

12.2 अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों और 2016 के नियमों के संयुक्त अध्ययन से, हमारी राय में, जहाँ भी 'बाल न्यायालय' या 'सत्र न्यायालय' शब्दों का उल्लेख किया गया है,

दोनों को वैकल्पिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए। इस अर्थ में कि जहाँ बाल न्यायालय उपलब्ध है, भले ही अपील सत्र न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य हो, उस पर बाल न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए। जबकि जहाँ कोई बाल न्यायालय उपलब्ध नहीं है, वहाँ सत्र न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाना है।

(ख) अधिनियम की धारा 15 के तहत बोर्ड के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का समय

13. यद्यपि, अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत प्रारंभिक मूल्यांकन के पश्चात धारा 18(3) के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध अधिनियम की धारा 15(2) एवं धारा 101(2) में अपील का अधिकार प्रदान किया गया है, तथापि, अपील दायर करने के लिए न तो कोई समय निर्धारित किया गया है और न ही आवश्यकता पड़ने पर विलम्ब के लिए क्षमा का कोई प्रावधान किया गया है।

13.1 हमारी राय में, यह एक चूक है। अधिनियम को व्यावहारिक बनाने और अपील के वैधानिक अधिकार के प्रयोग के लिए समयसीमा निर्धारित करने के लिए, जो हमेशा मौजूद है, हम इस अंतर को भरना उचित समझते हैं, जो अन्यथा अधिनियम की योजना के विरुद्ध नहीं है। इसलिए, धारा 101(2) में अपील दायर करने की अवधि के लिए, हम अधिनियम की धारा 101(1) से मार्गदर्शन लेते हैं। इसमें अपील दायर करने के लिए प्रदान की गई अवधि 30 दिन है और यदि पर्याप्त कारण दिखाया जाता है तो देरी को माफ करने की शक्ति भी अपीलीय प्राधिकारी को प्रदान की गई है। अपील के निर्णय के लिए समयसीमा भी प्रदान की गई है।

13.2 तदनुसार आदेश दिया गया।

(ग) दूसरी अपील के संबंध में

14. उपधारा (4) में यह प्रावधान है कि सत्र न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कोई द्वितीय अपील नहीं की जा सकेगी। उपधारा (5) में बाल न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान है, इसके लिए सीआरपीसी की प्रक्रिया लागू होती है, जैसे कि बाल न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील की जा सकती है। अधिनियम की धारा 102 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण शक्तियां भी प्रदान की गई हैं।

14.1 अधिनियम के प्रावधानों के सुचारू रूप से काम करने तथा विसंगतियों को दूर करने के लिए उपर्युक्त प्रावधानों की भी विस्तार से जांच की आवश्यकता होगी। हालांकि, चूंकि वर्तमान अपील में यह मुद्दा शामिल नहीं है तथा इस पर कोई तर्क नहीं दिया गया है, इसलिए हम इस मुद्दे को किसी उपयुक्त मामले में विचार के लिए खुला छोड़ते हैं।

V **05.04.2022 पर बोर्ड द्वारा पारित आदेश की वैधता**

15. वर्तमान मामले में, बाल एवं किशोर मनोचिकित्सा विभाग, निमहंस-डीडब्ल्यूसीओ द्वारा प्रस्तुत दिनांक 01.02.2022 की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें बोर्ड द्वारा सुनी गईं तथा दिनांक 29.03.2022 के आदेश के अनुसार मामले को 05.04.2022 को आदेश के लिए रखा गया। उस दिन, प्रधान मजिस्ट्रेट ने प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट और सामाजिक जांच रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात आदेश पारित किया कि सीसीएल पर बाल न्यायालय द्वारा एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना है। मामले के अभिलेखों को बाल न्यायालय, बेंगलुरु में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया। जब फाइल को हस्ताक्षर के लिए बोर्ड के सदस्य के समक्ष रखा गया, तो उन्होंने निम्नलिखित दर्ज किया:

"मैं उपरोक्त आदेश से असहमत हूँ। मैं अगली सुनवाई पर विस्तृत आदेश पारित करूँगा।"

15.1 मामले को 12.04.2022 पर रखने का निर्देश दिया गया था। अगली तारीख को, प्रधान मजिस्ट्रेट वहाँ नहीं होने के कारण और एक अन्य व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण, प्रधान मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में बोर्ड के दो सदस्यों द्वारा तर्कों को स्पष्ट रूप से सुना गया और यह निर्देश दिया गया कि सी. सी. एल. द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध की जांच बोर्ड द्वारा की जानी है।

15.2 अधिनियम की धारा 7 बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया से संबंधित है। इसकी उप-धारा 3 में प्रावधान है कि बोर्ड के किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति के बावजूद बोर्ड कार्य कर सकता है। बोर्ड द्वारा पारित कोई भी आदेश कार्यवाही के किसी भी चरण के दौरान किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अमान्य नहीं होगा। इसके परंतुक में प्रावधान है कि मामले के अंतिम निपटारे या अधिनियम की धारा 18(3) के तहत आदेश देने के समय प्रधान मजिस्ट्रेट सहित कम से कम दो सदस्य होंगे।

15.3 जब अधिनियम की धारा 18(3) के तहत आदेश के संदर्भ में मामले में दलीलें सुनी गईं और 29.03.2022 पर आदेश सुरक्षित रखा गया तो बोर्ड में एक प्रधान मजिस्ट्रेट और एक सदस्य शामिल थे।

15.4 अधिनियम की धारा 7(4) में प्रावधान है कि अंतरिम या अंतिम निपटान में कोई मतभेद होने की स्थिति में बहुमत की राय प्रबल होगी। जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां प्रधान मजिस्ट्रेट की राय प्रबल होगी।

15.5 अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि 29.03.2022 को आदेश सुरक्षित रखे जाने के बाद, मामले को 05.04.2022 को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया गया था। प्रधान मजिस्ट्रेट ने अपनी राय दर्ज की कि सीसीएल की सुनवाई बाल न्यायालय द्वारा की

जानी है। बोर्ड के अन्य सदस्य ने अपनी असहमति दर्ज की, हालांकि इस तरह के कोई विस्तृत कारण नहीं दिए गए। अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार, बहुमत की राय को ही मान्य माना जाता है। वर्तमान मामला उस श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि उस तारीख को बोर्ड में प्रधान मजिस्ट्रेट और एक सदस्य शामिल थे, और सदस्य ने अपनी असहमति दर्ज की थी। ऐसी स्थिति में प्रधान मजिस्ट्रेट की राय ही मान्य होगी। वर्तमान मामले में आदेश पर प्रधान मजिस्ट्रेट ने हस्ताक्षर किए थे। भले ही बोर्ड के दूसरे सदस्य ने आदेश पर हस्ताक्षर न किए हों और बिना कोई कारण दर्ज किए केवल यह उल्लेख किया हो कि उनका असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण है, प्रधान मजिस्ट्रेट का आदेश मान्य होगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी आदेश में कारण 'ह्रदय और आत्मा' होते हैं और अगले उच्च न्यायालय के लिए मामले की जांच करने में सहायक होते हैं। बोर्ड या बाल न्यायालय द्वारा सीसीएल की जांच या परीक्षण के संबंध में बोर्ड की राय के संदर्भ में कार्यवाही समाप्त हो गई है। उस मामले में आगे की कोई भी कार्यवाही असंवैधानिक और अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। इसके बारे में और कुछ कहना तो दूर की बात है। उस संबंध में उच्च न्यायालय की राय किसी हस्तक्षेप की मांग नहीं करती है।

VI **<u>अपील को स्वीकार करने की छूट</u>**

16. हमारी राय में, मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी को वह अधिकार दिया जाना चाहिए।

16.1 प्रारंभ में शिकायतकर्ता द्वारा दायर आवेदन को बोर्ड ने खारिज कर दिया था। उसी के खिलाफ व्यथित होकर, शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय ने बोर्ड की राय की अंतिमता के मुद्दे पर ही इसका फैसला किया। यह अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार था, जो यह प्रावधान करता है कि जहां

बहुमत की राय संभव नहीं है, वहां प्रधान मजिस्ट्रेट की राय प्रबल होगी। अपील एक मूल्यवान अधिकार है। बोर्ड द्वारा बाल न्यायालय द्वारा उसके मुकदमे का निर्देश देने वाले 05.04.2022 के आदेश के खिलाफ सीसीएल के पास जो भी तर्क हो सकते हैं, उन पर विचार नहीं किया गया है। आरोपित आदेश में केवल इस तथ्य पर ध्यान दिया गया कि बोर्ड ने निमहंस से प्राप्त राय पर विचार करने के बाद राय बनाई थी। यदि अधिनियम की योजना पर विचार किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 15 के तहत पारित बोर्ड के आदेश के खिलाफ अपील सत्र न्यायालय में होती है। अपीलीय प्राधिकरण, मुद्दों की जांच करने के लिए, अनुभवी मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करने का हकदार है, जिनकी सहायता बोर्ड द्वारा प्राप्त की गई है। इसलिए, स्वतंत्र जांच की परिकल्पना की गई है। इस मामले में उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। हम इस संबंध में पक्षों के अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं।

16.2 इसलिए, हमारा विचार है कि सीसीएल बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 05.04.2022 के आदेश के विरुद्ध 10 दिनों के भीतर अपील के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है और यदि कोई अपील दायर की जाती है, तो उसके बाद दो महीने के भीतर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उसका निर्णय किया जाएगा।

VII **<u>अतिरिक्त मुद्दे</u>**

17. निर्णय देने से पहले, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश के पैरा 25 को स्वीकृति के साथ उद्धृत करते हैं। नीचे उसका उद्धरण दिया गया है:

> "25. इस न्यायालय द्वारा एक और बिंदु यह देखा गया है कि आदेश पत्र और आदेशों पर हस्ताक्षर करते समय न्यायिक सदस्य के साथ-साथ गैर-न्यायिक सदस्यों के नाम उनके हस्ताक्षरों के नीचे नहीं लिखे जाते हैं। यह किसी के

लिए भी उपस्थित और अनुपस्थित सदस्यों के नाम जानने में बाधा बन रहा है। इसलिए, केवल हस्ताक्षरों के आधार पर, यह न्यायालय यह भेद करने में सक्षम था कि 05.04.2022 को कौन गैर-न्यायिक सदस्य उपस्थित था और 12.04.2022 को असहमति व्यक्त करने वाला तीसरा सदस्य कौन था। इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि सदस्यों के नाम उनके हस्ताक्षरों के नीचे उल्लेख करना उचित होगा, जिससे उक्त कार्यवाही के संचालन में पारदर्शिता लाने में भी मदद मिलेगी और सदस्यों को उक्त कार्यवाही में निभाई गई उनकी भूमिकाओं के बारे में सतर्क रहने में भी मदद मिलेगी।"

17.1 उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर गौर किया है जो पूरे देश में न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में उठता है। पीठासीन अधिकारी या बोर्ड के सदस्य, जैसा कि मामला है, या न्यायाधिकरण आदेश पारित करते समय अपने नाम का उल्लेख नहीं करते हैं। जिसके परिणामस्वरूप बाद में यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि न्यायालय या बोर्ड या न्यायाधिकरण की अध्यक्षता कौन कर रहा था या प्रासंगिक समय पर सदस्य कौन था। एक ही नाम के कई अधिकारी हो सकते हैं। जहां तक न्यायिक अधिकारियों का सवाल है, उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या जारी की गई है।

17.2 हम उम्मीद करते हैं कि जहां भी कमी हो, अदालतों, न्यायाधिकरणों, बोर्डों और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा पारित सभी आदेशों में, अंतरिम आदेशों सहित, हस्ताक्षर किए जाने पर आदेशों में पीठासीन अधिकारियों या सदस्यों के नाम विशेष रूप से उल्लिखित किए जाएँगे। यदि अधिकारियों को कोई पहचान संख्या दी गई है, तो उसे भी जोड़ा जा सकता है।

17.3 मामला यहीं खत्म नहीं होता। कई आदेशों में पक्षकारों और/या उनके वकीलों की उपस्थिति को ठीक से दर्ज नहीं किया गया है। इसके अलावा, यह स्पष्ट नहीं है कि किसके पक्ष में स्थगन मांगा गया और दिया गया। मामले के विभिन्न चरणों में इस तथ्य

पर विचार किया जाना बहुत प्रासंगिक है और यह भी पता लगाना चाहिए कि मामले में देरी करने वाला पक्ष कौन था। स्थगन देते समय, इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। यह लागत लगाने में भी सहायक हो सकता है, आखिरकार जब हम वास्तविक लागतों पर आते हैं।

VIII **राहतें और निर्देश**

18. हमारी उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, वर्तमान अपील का निपटारा निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता है:

(i) अधिनियम की धारा 14(3) का प्रावधान, जो अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन पूरा करने के लिए तीन महीने की अवधि प्रदान करता है, अनिवार्य नहीं है। इसे निर्देशिका माना जाता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से अवधि बढ़ाई जा सकती है।

(ii) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और 2016 के नियमों में 'बाल न्यायालय' और 'सत्र न्यायालय' शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर पढ़ा जाएगा। मुख्य रूप से अधिकार क्षेत्र बाल न्यायालय में निहित है। हालाँकि, जिले में ऐसे बाल न्यायालय के गठन की अनुपस्थिति में, अधिनियम के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति सत्र न्यायालय में निहित है।

(iii) अधिनियम की धारा 15 के तहत पारित बोर्ड के आदेश के खिलाफ अधिनियम की धारा 101(2) के तहत अपील 30 दिनों की अवधि के भीतर दायर की जा सकती है। अपीलीय अदालत उक्त अवधि की समाप्ति के बाद

अपील पर विचार कर सकती है, बशर्ते पर्याप्त कारण बताए गए हों। 30 दिनों की अवधि के भीतर दायर की गई ऐसी किसी भी अपील का फैसला करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(iv) वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग में कोई त्रुटि नहीं है।

(v) अधिनियम की धारा 7(4) के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया से संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.11.2023 को पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

(vi) 05.04.2022 को प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित बोर्ड द्वारा पारित आदेश अंतिम था। हालाँकि, यह पीड़ित पक्ष के अपील के अधिकार के अधीन है। अपीलकर्ता को आज से 10 दिनों की अवधि के भीतर उपरोक्त आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार होगा। अपीलीय प्राधिकारी दाखिल करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर इस पर निर्णय लेने का प्रयास करेगा।

(vii) न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, बोर्डों और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा पारित सभी आदेशों में पीठासीन अधिकारी और/या आदेशों पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के नाम का उल्लेख किया जाएगा। यदि कोई पहचान संख्या दी गई है, तो उसे भी जोड़ा जा सकता है।

(viii) पीठासीन अधिकारी और/या सदस्य आदेश पारित करते समय पक्षकारों और/या उनके वकीलों की उपस्थिति, जिस उद्देश्य के लिए मामला स्थगित किया जा रहा है और जिस पक्षकार की ओर से स्थगन मांगा गया है और दिया गया है, उसे उचित रूप से दर्ज करेंगे।

19. निर्णय की एक प्रति उच्च न्यायालयों के सभी रजिस्ट्रार जनरलों को भेजी जाए ताकि उसे न्यायिक अधिकारियों और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमियों के निदेशकों के बीच प्रसारित किया जा सके।

मामले का परिणाम: अपील का निपटारा किया गया।

* लेखक

† हाइनोट्स अंकित ज्ञान द्वारा तैयार किए गए